



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)  
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 472]  
No. 472]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 28, 1985/कार्तिक 6, 1907  
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 28, 1985/KARTIKA 6, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

## कृषि संज्ञासूचक

(कृषि और सहकारी विभाग)

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 1985

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्ति और निधियां  
लेखा, लेखा परीक्षा, परिसमापन तथा डिग्रियों, आदेशों और विनिश्चयों  
का निष्पादन) नियम, 1985

सा.का.वि. 812(अ) :—केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी  
सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 109 द्वारा  
प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1):—इन नियमों का संक्षिप्त नाम  
बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्ति और निधियां, लेखा,  
लेखा परीक्षा परिसमापन तथा डिग्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का  
निष्पादन) नियम, 1985 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा  
अपेक्षित न हो,—

(i) "अधिनियम" से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984  
(1984 का 51) अभिप्रेत है;

(ii) "प्राधिकृत अधिकारी" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 95 के  
प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;

(iii) "डिग्री" से किसी सिविल न्यायालय की कोई डिग्री अभिप्रेत  
है, और इसके अन्तर्गत धारा 85 में निर्दिष्ट कोई विनिश्चय  
या आदेश भी है;

(iv) "डिग्रीवार" से खंड (iii) में यथा परिभाषित डिग्री धारण  
करने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;

(v) "व्यतिक्रमी" से कोई ऐसा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी कोई  
सहकारी सोसाइटी, सदस्य या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति अभिप्रेत  
है जिसने व्यतिक्रम किया है;

(vi) "प्रकृष" से इन नियमों से उपाखण्ड प्रकृष अभिप्रेत है;

(vii) "साधारण अधिवेशन" से साधारण निकाय का, जिसके अन्तर्गत  
धारा 29 में निर्दिष्ट प्रतिनिधि साधारण निकाय भी है, अधि-  
वेशन अभिप्रेत है;

- (viii) "निर्णित श्रमण" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे कोई डिप्टी कमिश्नर को रोक लेना है ;
- (ix) "बहुसूत्री अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे धारा 85 के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;
- (x) "विक्रय अधिकारी" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्णित श्रमण की सम्पत्ति को कुर्क करने और उसका विक्रय करने के लिए या सम्पत्ति को कुर्क या विक्रय द्वारा किसी डिप्टी को निष्पादित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ;
- (xi) "घारा" से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ;
- (xii) उन शब्दों और पदों के जो अधिनियम में परिभाषित और प्रयुक्त प्रयुक्त हैं, किन्तु जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं ।

### अध्याय 2

बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के विशेषाधिकार, सम्पत्ति और निधियाँ

#### 3. बहियों में प्रविष्टि की प्रतियों का प्रमाणित किया जाना :—

(1) धारा 56 की उपधारा (i) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कार्यालय के सम्यक् अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई किसी बही में किसी प्रविष्टि की प्रति निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित की जाएगी—

- (i) सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक या सोसाइटी की उपबिधियों द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य सदस्य या कर्मचारी द्वारा ;
- (ii) जहाँ धारा 48 के अधीन बोर्ड का अधिकरण और प्रशासन की नियुक्ति करने वाला कोई आदेश पारित किया गया हो, वहाँ प्रशासन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ; और
- (iii) जहाँ धारा 80 की उपधारा (i) के अधीन, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के परिममाणक की नियुक्ति करने वाला कोई आदेश पारित किया गया हो, वहाँ परिममाणक द्वारा ।

(2) प्रत्येक प्रमाणित प्रति पर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की मुद्रा लगी होगी ।

4. सहकारिता शिक्षा निधि में अमिषाय :—(1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, प्रत्येक वर्ष अपने शुद्ध लाभों के एक प्रतिशत पर संगणित राशि अमिषाय के रूप में, भारत के राष्ट्रीय सहकारिता संघ लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अन्तर्गत सहकारिता शिक्षा निधि में जमा करेगी । सहकारिता शिक्षा निधि इस प्रयोजन के लिए नाम निर्दिष्ट समिति द्वारा प्रशासित होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (i) भारत के राष्ट्रीय सहकारिता संघ लिमिटेड नई दिल्ली का सभापति— अध्यक्ष
- (ii) केन्द्रीय रजिस्ट्रार— सदस्य
- (iii) वृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार— सदस्य
- (iv) बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के वा.प्रतिनिधि जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्येक दो वर्ष के लिए नाम-निर्दिष्ट किए जाएंगे— सदस्य
- (v) महानिदेशक, राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली— सदस्य
- (vi) निदेशक, वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारिता प्रबंध संस्थान, पुणे— सदस्य

(2) सहकारिता शिक्षा निधि का उपयोग सदस्यों की शिक्षा और सहकारिताओं के लिए सामान्य विकास से संबंधित प्रयोजनों के लिए किया जाएगा ।

5. शुद्ध लाभों का व्ययन :—प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शुद्ध लाभों का संविमरण या उपयोग निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहने हुए किया जाएगा :—

- (क) कोई भी लाभांश, शुद्ध लाभों में के विधाय प्रेषित या संभल नहीं किया जाएगा और समादल शेयर पूंजी पर 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा ।
- (ख) कोई भी लाभांश प्रेषित या संभल नहीं किया जाएगा यदि किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का कोई वादा, किसी निक्षेपकर्ता या उधार देने वाले के पास अनुरुद्ध रहता है ।
- (ग) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी वर्ष के शुद्ध लाभों में दिया गया कोई दान पाँच लाख रुपये से अधिक नहीं होगा ।

6. निधियों का विनिधान :—(1) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, अपनी निधियों को निम्नलिखित किसी एक या अधिक ढंगों में विनिधित या निक्षेप कर सकेगी :—

- (i) धारा 62 के खंड (क) में (ड) में उपबंधित कोई ढंग ;
- (ii) कोई डाकघर बचत बैंक ;
- (iii) केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा बालू की गई कोई बचत स्कीम ;
- (iv) किसी निगम या अन्य निगमित निकाय के ऐसे शेयरों में जिसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार या दोनों पचास प्रतिशत से अधिक शेयरों के धारक हैं ; और
- (v) किसी निगम या निगमित निकाय द्वारा जारी किए गए डिबेंचर यदि ऐसे डिबेंचर केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्याभूत हैं ।

7. आरक्षित निधि के उद्देश्य और विनिधान :—(1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, निम्नलिखित एक या अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आरक्षित निधि बनाए रखेगी :—

- (i) अकल्पित हानियाँ ;
- (ii) सोसाइटी के वैनदरों के दावे जिन्हें अन्यथा पूरा नहीं किया जा सकता ; और
- (iii) विशेष कमी की वशा में ऐसी अन्य वित्तीय आवश्यकताएँ ।

(2) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की अनुज्ञा से अपनी आरक्षित निधि का निम्नलिखित में विनिधान या निक्षेप कर सकेगी :—

- (i) (क) अपने कार्यालय, कर्मचारिबृन्द या उपकरण, (ख) अपनी मशीनरी या संयंत्र के संस्थापन या प्रचालन के लिए भूमि और भवन के ऋय या अर्जन और भवन निर्माण के लिए ;
- (ii) मशीनरी या संयंत्र का ऋय जो उसके मुख्य कार्यालय के लिए अपेक्षित है ;
- (iii) खंड (i)(क) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए भूमि और भवन के ऋय या अर्जन और भवन-निर्माण के लिए तथा उसकी उप-बिधियों के उपबंधों के अनुसार उनके सदस्यों के फायदे के लिए भी, और
- (iv) अपना कार्यालय ।

(3) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आरक्षित निधि कबिमाज्य हांगी और किसी भी सदस्य का उसमें कोई दावा या शेयर नहीं होगा।

(4) कोई भी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जिसकी आरक्षित निधि पृथक रूप में विनिहित या निक्षेप की गई है, ऐसी निधि का, केन्द्रीय रजिस्ट्रार की पूर्व प्राप्त मंजूरी के बिना, आहरण नहीं करेगा, गिरवी नहीं रखेगा या अन्यथा काम में नहीं आएगा।

(5) उपनियम (1) में उल्लिखित उद्देश्यों के लिए आरक्षित निधि का उपयोग इस शर्त के अधीन रहने हुए होगा कि निकाली गई किसी राशि का पञ्चाशत्तम सहकारी वर्ष या वर्षों में उपभोग होने वाले लाभों में प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसा कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित किया जाए। स्थापित, केन्द्रीय रजिस्ट्रार सोसाइटी की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस बात की अनुमति दे सकेगा कि उपनियम (1) के खंड (ii) और (iii) के अन्तर्गत उल्लिखित उद्देश्यों के लिए निकाली गई और उपयोग की गई आरक्षित निधि की पूर्णतः या अंशतः प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी, जैसा कि वह निर्देशित करे।

(6) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के परिचालन की दशा में बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आरक्षित निधि और अन्य निधियों का नीचे मद् (i) में (ii) में विनिर्दिष्ट पृथक्ता के अनुसार पहले बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के दायित्वों के उन्मोचन में, उपयोजन किया जाएगा:—

- (i) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कर्मचारियों की शोध्य वेतन या अन्य संदाय, यदि कोई हो;
- (ii) कर्मचारियों के प्रतिभूति निक्षेप, यदि कोई हो;
- (iii) सरकार से लिया गया या सरकार की प्रत्याभूति पर लिया गया उधार, यदि कोई हो;
- (iv) गैर सदस्यों के निक्षेप, यदि कोई हों;
- (v) ऋण, यदि कोई हों; और
- (vi) सदस्यों के निक्षेप, यदि कोई हों।

(ख) खंड (क) में उल्लिखित दायित्वों के उन्मोचन के पश्चात् अतिशेष, यदि कोई हो, उपयोजन समाप्त शेयर पूंजी का प्रतिसंदाय करने के लिए और तत्पश्चात् जहां वह संदेत नहीं किया गया हो, वहां लाभांश या संदाय करने के लिए किया जाएगा।

(ग) खंड (ख) में किसी बात के होते हुए भी यदि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में लाभांश के संदाय का उपबंध नहीं है, तो कोई लाभांश संदेत नहीं किया जाएगा।

(7) उपनियम (6) में उल्लिखित संदायों के पश्चात् शेष रह गये किसी अधिशेष का उपयोजन समायक द्वारा सदस्यों से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय रजिस्ट्रार के अनुमोदन के अधीन रहने हुए नियम 4 में निविष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा निधि या सहकारी शिक्षा निधि में अभिदाय के लिये या किसी अन्य पूर्व प्रयोजन या लांकोपयोगी स्थानीय उद्देश्यों के लिये किया जायेगा।

8. दुर्घत ऋणों और हानियों को बट्टेखाते डालना:— ऐसे सभी ऋण, जिसमें उस पर ब्याज और उसकी बाबत बसूली प्रचार भी सम्मिलित है, जो अग्रमूर्तीय पाये जाये और जिन्हें धारा 67 के अधीन नियुक्त लेखा परीक्षक द्वारा दुर्घत ऋण के रूप में प्रमाणित किया जाये, पहले दुर्घत ऋण निधि के मद् बट्टेखाते डाले जायेंगे और प्रतिशेष यदि कोई हो, आरक्षित निधि और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की शेयर पूंजी के मद् अपलिखित किया जा सकेगा।

अन्य सभी शोध्यों और मंचित हानियों के या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा उठाई गई किसी अन्य हानियों, जिसे मूल न किया जा सके, और जिसे लेखापरीक्षक द्वारा अवमूर्तीय प्रमाणित कर दिया गया

हो, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आरक्षित निधि के मद् अपलिखित किया जा सकता है:—

परन्तु—

- (क) कोई दुर्घत ऋण या हानियां साधारण निकाय की मंजूरी के बिना अपलिखित नहीं की जायेंगी;
- (ख) ऐसे किसी दुर्घत ऋण या हानियों को अपलिखित करने से पहले बहुराज्य सहकारी सोसाइटी केन्द्रीय रजिस्ट्रार का अनुमोदन प्राप्त करेगी।

परन्तु और कि केन्द्रीय रजिस्ट्रार अनुमोदन करते समय, दुर्घत ऋण की प्रतिपूर्ति और आरक्षित निधि के मद् अपलिखित रकम का प्राथिक या पूर्ण प्रत्यावर्तन भविष्य में होने वाले लाभों से करने की बाबत ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

9 गैर सदस्यों के साथ संभवहार:— धारा 65 में अन्यथा उपबंधित का छोड़कर और केन्द्रीय रजिस्ट्रार की साधारण या विशिष्ट मंजूरी के बिना कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी किसी सदस्य से किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई उधार विषयक संभवहार तब तक नहीं करेगी जब तक कि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियां ऐसे संभवहार करने की अनुमति नहीं देती।

10. ऋण के लिये आवेदन:— (1) ऋण के लिये आवेदन ऐसे प्रारूप में होगा जैसा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा अपेक्षित हो और उसमें उस प्रयोजन का जिसके लिये ऋण अपेक्षित है सोसाइटी की उपविधियों में अधिकृत रीति में कथन किया जायेगा।

(2) प्रत्येक ऋण के लिये सदस्य ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा जिसकी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों के अधीन अपेक्षा की जाये।

(3) ऋण के प्रतिसंदाय की अवधि ऐसी होगी जो उपविधियों में उपबंधित हो किन्तु किसी भी दशा में यह अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी में, जिसमें सदस्यों का दायित्व शेयर के आधार पर परिसीमित हो, किसी सदस्य को उसके द्वारा संदेत शेयर पूंजी की रकम के दस गुने से या उससे जो उपविधि में अधिकृत हो, अधिक ऋण मंजूर नहीं किया जायेगा।

11. अभिदायी भविष्य निधि:— (1) प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी जिसकी सेवा में पांच या उससे अधिक नियमित कर्मचारी हैं, धारा 66 की उपधारा (1) में निविष्ट अभिदायी भविष्य निधि की स्थापना करेगी।

(2) ऐसी निधि सृजित करने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी उपविधियों में निम्नलिखित का उपबंध करेगी:—

- (क) निधि का प्रशासित करने के लिये प्राधिकारी।
- (ख) कर्मचारियों के वेतन से कटौती किये जाने वाले अधिदाय की राशि।
- (ग) कर्मचारी की मृत्यु की दशा में अभिदायी भविष्य निधि की रकम के संदाय के लिये नामनिर्देशन की रीति।
- (घ) प्रयोजन जिसके लिये वह सीमा तक जिस तक और वह अवधि जिसके पश्चात् ऐसी निधि की प्रतिपूर्ति के विषय अधिम विद्ये जा सकेंगे। और मासिक किस्तों की वह संख्या जिनमें अधिम प्रतिसंदाय किया जायेगा।

(ङ) कर्मचारी अभिदाय और सोसाइटी द्वारा किये गये अभिदाय का प्रतिदाय।

(क) ऐसी निधि के लेखा का रख-रखाव ।

(3) अभिदाय की वह रकम जिसकी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के किसी कर्मचारी के वेतन से कटौती की जा सकती है, उसके मासिक मूल वेतन के 8.33 प्रतिशत से कम नहीं होगा ।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी प्रत्येक वर्ष कर्मचारी अभिदायी भविष्य निधि में ऐसा अभिदाय कर सकेगी जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाये । ऐसे अभिदाय की रकम कर्मचारी के मूल वेतन के 8.33 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

12. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के परिसीमित दायित्व के उधारों पर निर्बंधन:—परिसीमित दायित्व वाली कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी समावृत्त शेयर पूंजी जमा संबंधित आरक्षितियों घटा हानियों की राशि के दस गुने से अधिक का निक्षेप या ऋण स्वीकार नहीं करेगी या किसी अन्य रीति से दायित्व उत्पन्न नहीं करेगी ।

परन्तु केन्द्रीय रजिस्ट्रार लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को उपरोक्त सीमा से अधिक दायित्व उत्पन्न करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

13. नकद स्रोतों का अनुरक्षण और आस्तियों का विवरण:—प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी, जो अपनी कामकाज पूंजी का कोई अंश निक्षेपों द्वारा प्राप्त करती है,—

(क) ऐसे नकद स्रोत जिसे प्रथम में जो उन बहुराज्य सहकारी प्रत्यक्ष सोसाइटियों की दशा में जो बैंककारी विधियुक्त अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की परिधि के अन्तर्गत आती है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा और अन्य बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों की दशा में केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, बनाये रखेगी, और

(ख) अपनी कामकाज पूंजी के केवल ऐसे अंश का उपयोग उधार देने के कारबार में करेगी और अपनी आस्तियों का वितरण ऐसे मानकों के अनुसार करेगी जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किये जायें ।

14. शेयर जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को आबमानित नहीं किये जायेंगे:—किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के शेयरों को उसके सदस्यों द्वारा ऋण के लिये प्रतिभूति के रूप में आबमानित नहीं किया जायेगा ।

15. नैर-सदस्यों की प्रतिभूति पर ऋण:—कोई बहुराज्य सहकारी सोसाइटी किसी नैर-सदस्य द्वारा दिये गये किसी प्रतिभूति बंधपत्र के आधार पर किसी सदस्य को कोई ऋण नहीं देगी :

परन्तु केन्द्रीय रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के किसी वर्ग को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा ।

### अध्याय 3

#### लेखा परीक्षा और लेखे

16. लेखा-बही—प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी निम्नलिखित की दायित्व लेखा-बही रखेगी —

(क) प्राप्त और व्यय किये गये धन की सभी धन राशियां और वे मामले जिनके संबंध में प्राप्तियां और व्यय किये जाते हैं;

(ख) माल के सभी विक्रय और क्रय;

(ग) आस्तियां और दायित्व;

(घ) ऐसी किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की दशा में जो उत्पादन, प्रसंस्करण और विनिर्माण में लगी हुई है सामग्री या श्रमिकों या लागत की अन्य मूल्यों के उपयोग से संबंधित ऐसी विशिष्टियां जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें ।

17. लेखापरीक्षा की विषय वस्तु:—धारा 67 की उपधारा (1) के अधीन किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की लेखापरीक्षा के अन्तर्गत उस धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट मामलों के प्रतिरिक्त, निम्नलिखित विशिष्टियां भी होंगी:—

(क) क्या लेखापरीक्षक ने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिये हैं, जो उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक है ;

(ख) क्या उसकी राय में इन नियमों और उपविधियों में यथा विनिर्दिष्ट उचित लेखा बहियां बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा रखे गई हैं, जहां तक यह उन बहियों की जांच से प्रतीत होता है और उसकी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिये समुचित उचित विवरणियां उन शाखाओं से प्राप्त हो गई हैं, जहां वह नहीं जा सका है ;

(ग) क्या उसकी सर्वोत्तम जानकारी और उसको दिये गये तथा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की बहियों द्वारा यथावशित स्पष्टीकरण के अनुसार सुलनवश और लाभ और हानि लेखा से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कामकाज की सही और उचित स्थिति का पता चलता है; और

(घ) क्या व्ययों में या बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को शोध्य धन की बसूली में और तात्त्विक अनौचित्य या अभिव्यक्तता हुई है ।

(2) जहां उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में उत्तर किसी टिप्पण सहित नकारात्मक या सकारात्मक रूप में हो, वहां लेखापरीक्षक ऐसे टिप्पण के समर्थन में तथ्य और आंकड़े देकर ऐसे उत्तर के कारण देगा ।

(3) लेखापरीक्षा रिपोर्ट में निम्नलिखित की विशिष्टियों की बाधत कुछ अनुसूचियां भी संलग्न होंगी:—

(क) ऐसे सभी संयोजक जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अधिनियम, नियमों या उपविधियों के उपबन्धों के प्रतिकूल प्रतीत होते हों;

(ख) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी या कोई धन जो लेखा परीक्षक को दुर्बल या बसूली के लिये शंकास्पद प्रतीत हों;

(ग) बोर्ड के सदस्यों को बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा दिये गये उधार; और

(घ) कोई अन्य विषय जो केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये जायें ।

(4) लेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट बहुराज्य सहकारी सोसाइटी को देगा और उस रिपोर्ट की एक प्रति सीधे केन्द्रीय रजिस्ट्रार को भी भेजेगा ।

केन्द्रीय रजिस्ट्रार लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से यह निवेश दे सकेगा कि यदि लेखापरीक्षा रिपोर्ट का ऐसा कोई भाग जो उसे आक्षेपणीय प्रकृति का प्रतीत हो या जो न्यायोजित नहीं है निकाल दिया जायेगा और इस प्रकार निकाला गया भाग लेखापरीक्षा रिपोर्ट का भाग नहीं होगा ।

(5) लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई लेखापरीक्षा रिपोर्ट पर किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा और उसे उनकी टिप्पणी के साथ साधारण अधिवेशन के समक्ष रखा जायेगा ।

(6) लेखापरीक्षकों द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के कार्यकरण में बताई गई त्रुटियों पर बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से विचार किया जायेगा और त्रुटियों को सुधारने के लिये किये गये उपायों को स्पष्ट करते हुए, एक अनुपालन रिपोर्ट लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्राप्त होने के तीन मास के भीतर केन्द्रीय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायेगी।

## अध्याय—4

## बहुराज्य सहकारी सोसाइटीयों का परिसमापन

19. समापक द्वारा अपनाये जाने वाली प्रक्रिया—जहां द्वारा 80 की उपधारा (1) के अधीन किसी परिसमापक नियुक्त किया गया है वहां निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:—

- (क) समापक को नियुक्ति को केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जायेगा।
- (ख) जैसे ही बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का आदेश प्रभावी होता है समापक ऐसे माध्यामों द्वारा जो वह उचित समझे, एक सूचना प्रकाशित करेगा जिसमें ऐसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध जिसके परिसमापन का आदेश किया गया है, सभी दावों के सूचना के प्रकाशन के दो मास के भीतर समापक को प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा की जायेगी।

किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का लेखा बहियों में अभिलिखित सभी दायित्व स्वयं ही समापक के दाय खंड के अधीन उन्मूलन रूप में प्रस्तुत किये गये समझे जायेंगे।

- (ग) समापक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के विरुद्ध किये गये सभी दावों का अन्वेषण करेगा और दावेदारों के बीच उद्भूत होने वाले पूर्विकता के प्रश्नों का विनिश्चय करेगा।
- (घ) समापक, सभी धन राशियां और अन्य संपत्तियां जिनको बहुराज्य सहकारी सोसाइटी हकदार है, वसूल करेगा और उस प्रयोजन के लिये ऐसे वाद या समापन कार्यवाहियों लिये अनुबंधित ऐसे वाद जो वह उचित समझे, संस्थित कर सकेगा।
- (ङ) समापक लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को अपनी ओर से वसूली करने के लिये और विधिमाम्य रसीद देने के लिये सशक्त कर सकेगा।
- (च) समापक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों और दायित्वों का, जैसे कि समापन के आदेश करने की तारीख को थे, परिनिवारण करने के पश्चात्, धारा 81 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों के लिये उसके सदस्यों भूतपूर्व सदस्यों या संपदा या नामनिर्देशिता वारिस या मृत सदस्यों के विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा समय समय अंशदान जिसके अन्तर्गत समापन के लिये देय ऋण और खर्च भी है, का अवधारण करने की अगली कार्यवाही करेगा। यदि आवश्यकता हो तो वह ऐसे अभिदायों की बाबत समनुषंगी आदेश भी कर सकेगा और ऐसा आदेश मूल आदेश की भांति प्रवर्तनीय होगा।
- (छ) समापक के भारसाधन में की सभी निधियां डाकपर बचत बैंक या किसी सहकारी बैंक या ऐसे किसी अन्य बैंक में जिसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाये, जमा की जायेंगी और उसके नाम में रहेंगी।
- (ज) केन्द्रीय रजिस्ट्रार समापक को संदत्त की जाने वाली पारिश्रमिक की रकम, यदि कोई हो, नियत करेगा। पारिश्रमिक समापन की रकम में सम्मिलित होगा जो सभी अन्य दावों की पूर्विकता में, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों में से संदेय होगा।

(झ) समापक, समापन के अधीन बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों का अधिवेशन बुला सकेगा।

(ञ) समापक ऐसे प्ररूप में जिसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के समापन में हुई प्रगति का वर्णन वाली एक निमाही रिपोर्ट केन्द्रीय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा।

(ट) समापक ऐसी बहियां और लेखाओं को बनाये रखेगा जिसे समय समय पर केन्द्रीय रजिस्ट्रार विनिर्दिष्ट करे और वह किसी भी समय ऐसी बहियों और लेखाओं की लेखापरीक्षा करा सकेगा।

(ठ) समापन की समाप्ति पर, समापक विघटित सोसाइटी के सदस्यों का एक साधारण अधिवेशन बुलायेगा और उसमें समापक को उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में विशेष या साधारण आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अपनी कार्यवाहियों के परिणाम का संक्षिप्त विवरण देगा और अन्य अधिशेष निधियों के व्ययन के बारे में मत देगा। समापक अपनी अन्तिम रिपोर्ट, उर्रोक्त निदिष्ट साधारण अधिवेशन की कार्यवाहियों की प्रति के साथ, केन्द्रीय रजिस्ट्रार को देगा और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की सभी बहियों और रजिस्ट्रारों तथा लेखाओं आदि को और उसके द्वारा समापन कार्यवाही से संबंधित सभी बहियों और लेखाओं को केन्द्रीय रजिस्ट्रार को सौपेगा।

(ड) यदि समापक द्वारा किसी दायित्व का उन्मोचन इस कारण से कि दावेदारों के पत्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं है या कोई अन्य कारण से नहीं किया जाता है तो ऐसे अनुमोचित दायित्व के अन्तर्गत आने वाली रकम को किसी सहकारी बैंक में जमा किया जा सकेगा और वह संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के दावों को पूरा करने के लिये उपलब्ध रहेगी।

(ड) किसी समापक को किसी भी समय केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा हटाया जा सकेगा और इस प्रकार हटाये जाने पर वह समापन के अधीन सोसाइटी से संबंधित सभी सम्पत्ति और दस्तावेज किसी ऐसे व्यक्तियों को देने के लिये जाबज्ज होगा, जिसे केन्द्रीय रजिस्ट्रार निर्दिष्ट करे।

(ण) किसी ऐसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की, जिसका रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है, और बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के समापन की कार्यवाहियों का परिसमापन करने का आदेश कर दिया गया है, सभी बहियां और अभिलेख केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के रजिस्ट्रारकरण के रद्द किये जाने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् नष्ट किये जा सकेंगे।

20. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों का उपयोजन :— बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की आस्तियों का उपयोजन दायित्वों के संदाय के लिये निम्नलिखित पूर्विकता क्रम में किया जायेगा :—

- (1) सभी बाहर के दायित्वों का अनुपातिक संदाय
- (2) सदस्यों के उधारों और निक्षेपों का अनुपातिक प्रतिसंदाय
- (3) शेयर पूंजी का अनुपातिक प्रतिसंदाय
- (4) समापन की अवधि के लिये प्रति वर्ष 6—25 प्रतिशत से अधिक की दर पर शेयर पर लाभांश का अनुपातिक संदाय।

21. अधिशेष आस्तियों का व्ययन :—धारा 82 की उपधारा (ख) के प्रयोजन के लिये अधिशेष आस्तियों को सदस्यों द्वारा धारित शेयर पूंजी के अनुपात में या सदस्यों द्वारा बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के साथ किये गये कारबार के अनुपात में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 82 के उपखंड (ख) के अधीन मंजूरी देने से पूर्व अवधारित की जाये वितरित किया जायेगा।

## अध्याय—5

## डिज़ियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन

22 डिज़ियों, आदेशों और विनिश्चयों के निष्पादन की प्रक्रिया

(1) कोई भी डिज़ीदार जो धारा 85 के खंड (ग) के उपबन्धों का मांग किये जाने की अपेक्षा करता है, उस बसुली अधिकारी का आवेदन देगा जिसकी अधिकारिता में वह तत्काल उद्भूत हुआ था और केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा निम्न किये गये आवश्यक खर्च उभारा करेगा। यदि निजीत श्रुति का निवास स्थान या वह सम्पत्ति, जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, ऐसे बसुली अधिकारी की अधिकारिता के बाहर स्थित है तो वह बसुली अधिकारी उस बसुली अधिकारी के पास आवेदन को अन्तर्गत कर देगा जिसकी अधिकारिता में निजीत श्रुति रहता है या सम्पत्ति स्थित है।

(2) प्रत्येक ऐसा आवेदन, केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित प्ररूप में दिया जायेगा और डिज़ीदार द्वारा हस्ताक्षरित होगा। डिज़ीदार यह उपदर्शित करेगा कि क्या वह डिज़ीदार को बंधक की गई स्यावर सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही करना या जंगम सम्पत्ति की कुर्की प्राप्त करना चाहता है।

(3) ऐसा आवेदन प्राप्त होते पर बसुली अधिकारी, केन्द्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय में अधिलेखा। यदि कोई हो, के साथ आवेदन में उपबन्धित विनिश्चित की श्रुति और अवधारणा का मसौदा करेगा और केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित प्ररूप में व्यक्तिकर के नाम की ओर देय रकम को उपबन्धित करने हुए लिखित में दो प्रतियों में एक मांग सूचना तैयार करेगा और उसे विषय अधिकारी को भेजेगा।

(4) जब तक कि डिज़ीदार अपनी यह वाछा व्यक्त नहीं करता है कि कार्यवाहियों उपनिर्देश (2) में अधिकांशतः किसी विशिष्ट नाम में की जानी चाहिए, निष्पादन सामान्यतः निम्नलिखित रीति से किया जाएगा—

(i) पहले व्यक्तिकर की जंगम सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, किन्तु इससे आवश्यकता की दशा में माय-माय स्यावर सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने से प्रभावित नहीं होगा।

(ii) यदि कोई जंगम सम्पत्ति नहीं है, या यदि जंगम सम्पत्ति के विक्रय-आगम, या कुर्की की गई और विक्रय की गई सम्पत्ति में डिज़ीदार की मांग पूर्णतः पूरी नहीं होती है तो डिज़ीदार को बंधक की गई स्यावर सम्पत्ति या व्यक्तिकर की अन्य स्यावर सम्पत्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) जंगम सम्पत्ति के अधिग्रहण और विक्रय करने में निम्नलिखित नियमों का अनुपालन किया जाएगा—

(क) विषय अधिकारी, डिज़ीदार को पूर्व सूचना देने के पश्चात् उस ग्राम में या स्थान पर, जहाँ व्यक्तिकर निवास करता है या करस्थम् की जाने वाली सम्पत्ति स्थित है, जाएगा और यदि व्यक्तिकर उपस्थित हो तो उसे मांग सूचना तामील करेगा। यदि व्यक्तिकर मृत्यु देय रकम का संदाय करने नहीं किया जाता है तो विषय अधिकारी करस्थम् तैयार करेगा और करस्थम् की गई सम्पत्ति की सूची या तादिका व्यक्तिकर को दूरकर देगा तथा यदि देय रकम का पहले उन्मोचन नहीं किया गया है तो करस्थम् की गई सम्पत्ति के विक्रय के स्थान, दिन और समय की सूचना देगा। यदि व्यक्तिकर अनुपस्थित हो, तो विषय अधिकारी, उसके कट्टर के किसी वयस्क पुरुष सदस्य को या उसके प्राधिकृत अधिकारी को मांग सूचना तामील करेगा या जब ऐसी तामील न हो सके तो वह उस के निवास स्थान के सहजदुध में मांग पर मांग सूचना की प्रति लगा देगा। उसके पश्चात् वह करस्थम् की कार्य-

वाही करेगा और व्यक्तिकर के निवास स्थान के प्राधिकर स्थान पर कुर्की की गई सम्पत्ति की सूची, उस पर यह स्थान, जहाँ सम्पत्ति प्रस्तुत की जा सकेगी और विक्रय का स्थान, दिन और समय, पृथक्कृत करने हुए, लगाएगा।

(ख) करस्थम् करने के पश्चात्, विषय अधिकारी डिज़ीदार द्वारा या अन्यथा कुर्की की गई सम्पत्ति की अधिग्रहण का प्रबंध करेगा। यदि विषय अधिकारी डिज़ीदार में सम्पत्ति की अधिग्रहण का निम्मा लेन की अपेक्षा करता है, तो वह ऐसा करने के लिए बाध्य होगा और उसकी उपेक्षा के कारण उपगत किसी हानि की डिज़ीदार प्रति करेगा। यदि कुर्की की गई सम्पत्ति पण्डित है, तो डिज़ीदार उसके आवश्यक खर्च उपलब्ध करने के लिए जिम्मेदार होगा। विषय अधिकारी, उसे व्यक्तिकर या ऐसी सम्पत्ति में किसी हानि का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के प्रत्यक्ष पर, राम ने या उस स्थान पर, जहाँ उसे कुर्की किया गया था, ऐसे व्यक्तिकर या व्यक्ति के भारसाधन में उस दशा में छोड़ देगा, यदि वह केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित प्ररूप में, सम्पत्ति की, जब अपेक्षा की जाए, प्रस्तुत करने के लिए एक या अधिक पण्डित प्रतिबन्धों सहित एक बंधपत्र लिखता है।

(ग) करस्थम् सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त से पूर्व किया जाएगा और किसी अन्य समय पर नहीं।

(घ) उद्गृहीत करस्थम् पश्चात्कि नहीं होगा, अर्थात्—करस्थम् की गई सम्पत्ति, व्यक्तिकर द्वारा व्याज सहित देय राशि और करस्थम् विरुद्ध तथा विषय के आन्तरिक मनी खर्च का श्रमान्त निकटतम अनुपातिक होगा।

(ङ) यदि व्यक्तिकर की भूमि की फसल या उद्गृहीत उत्पाद का कुर्की किया जाता है, तो विषय अधिकारी, उन्हें तब विक्रय करेगा, जब वे कटाई या संग्रहण के लिए उपयुक्त हों या अपने विक्रय पर सम्पत्ति मोसम में कटाएगा या संग्रह करेगा और विक्रय किए जाने तक उन्हें समुचित स्थान में रखेगा। पञ्चावर्षीय मामले में, ऐसी फसल या उत्पाद की कटाई या संग्रहण और भण्डारण का खर्च स्वामी द्वारा उनकी सम्पत्ति का मोचन करने पर या उसका विक्रय किए जाने की दशा में विक्रय के आगम में दाख किया जाएगा।

(च) विषय अधिकारी, बैलों या पशुओं से कार्य नहीं करेगा या करस्थम् किए गए माल या जीववस्तु माल का उपयोग नहीं करेगा और वह पशुओं तथा पशुधन के लिए आवश्यक खर्च की व्यवस्था करेगा उसमें होने वाले खर्च, स्वामी द्वारा अपनी सम्पत्ति का मोचन कराने पर या सम्पत्ति के विक्रय किए जाने की दशा में विक्रय के आगम से अदा किया जाएगा।

(छ) विषय अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी अन्तर्गत, गोशाला, धान्य भण्डार, गोशाला, उद्गृह या अन्य भवन को बलपूर्वक खुला ले और वहाँ किसी निवास-गृह में भी प्रवेश कर सकेगा, जिसका आदर दरवाजा खोल सकेगा और किसी व्यक्तिकर की सम्पत्ति को कुर्की करने के प्रयोजन के लिए ऐसे निवास-गृह में किसी कक्ष के दरवाजे को खोल सकेगा और उसमें दाखिल हो सकेगा, परन्तु इसमें इसके पश्चात् उपबन्धित के सिवाय अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह ऐसे निवास-गृह के खंड को, जो जनानखाना या महिलाओं के निवास के लिए अलग रखा गया है, खोलें या उसमें प्रवेश करें।

(अ) जहाँ विषय अधिकारी के पास यह अनुमान लगाने का कारण हो कि किसी व्यक्तियों की संपत्ति, किसी ऐसे निवासगृह में, जिसका बाह्य दरवाजा बन्द हो या जिसमें ऐसे खंडों के भीतर, जो महिलाओं के लिए अलग रखे गए हैं, जिन्हें पति या प्रयाग आधार पर प्राईवेट समझा जाता है, जमा की गई है, वहाँ विषय अधिकारी निकटतम पुलिस थाने के शारमाधिक अधिकारी को तत्पक्ष अध्यावेदन करेगा। उक्त पुलिस थाने का शारमाधिक अधिकारी ऐसे अध्यावेदन पर, किसी पुलिस अधिकारी को उस स्थान पर भेजेगा जिसकी उपस्थिति में, विषय अधिकारी ऐसे निवास गृह का वक्ता दरवाजा उसी रीति से अनपेक्षित खोलना सकेगा जिस प्रकार वह जमानाधार के निवास गृह के भीतर किसी कक्ष के दरवाजे को लुइवा कर खोल सकता है। विषय अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में, जमानाधार के भीतर से महिलाओं को हटाने के लिए सम्यक् सूचना देने के पश्चात् और यदि वे महिलाएं ऐसे करने में हैं, जो रहि या प्रयाग के अनुसार गार्ड-जैतिक रूप में प्रकट नहीं हो सकती, तो किसी उपयुक्त रीति में उन्हें हटाने के लिए साधन लेकर, व्यक्तियों की उनके जमा संपत्ति, यदि कोई है, का करस्थान करने के प्रयोजन के लिए जनता खंडों में भी प्रवेश कर सकेगा; किन्तु ऐसी संपत्ति, यदि पाई जाए तो, को ऐसे खंडों से तुरंत हटा लिया जाएगा, उसके पश्चात् उसे पूर्ववर्ती अधिभोगियों के लिए मुक्त छोड़ दिया जाएगा।

(अ) विषय अधिकारी, विषय से एक दिन पहले और विषय के दिन ग्राम में या उस स्थान पर, जहां व्यक्तियों निवास करता है, जाए जाने वाले आणवित विषय की समय और स्थान के बारे में छोटी पिटवा कर विषय की तारीख से पहले लगातार दो दिन और विषय प्रारंभ होने से पूर्व विषय के दिन और किसी ऐसे स्थान या स्थानों पर, जिन्हें अधिकारी विषय के सम्यक् प्रचार देने के लिए आवश्यक समझे, उद्घोषणा करवाएगा। उस तारीख से, जिसको विषय सूचना खंड (क) में विहित रीति में तारीख की गई या चिपकाई गई है, 15 दिन की अवधि की समाप्ति तक कोई विषय नहीं होगा :-

परन्तु जहां अधिग्रहण की गई संपत्ति शीघ्रता और प्रश्रय्य धारणीय है या जहां उसे अधिग्रहण में रखने का खर्च उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना है, वहाँ विषय अधिकारी, जब तक कि देय राशि उससे पहले संभल नहीं कर दी जाती, 15 दिन की उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय उसका विषय कर सकेगा।

(अ) नियत समय पर संपत्ति को एक या एक से अधिक तारों में, जो विषय अधिकारी उचित समझे, रखी जाएगी और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले से विषय कर दी जाएगी।

परन्तु विषय अधिकारी इस बात के लिए स्वयं होगा कि यह सबसे ऊंची बोली को, जहां प्रस्तावित कीमत सम्यक् रूप से कम प्रतीत होती हो वहां या अन्य कारणों से स्वीकार करने से इन्कार कर दे; जहां संपत्ति का देय राशि से अधिक पर विषय किया जाता है, वहां अधिग्रहण रकम को ब्याज और प्रश्रय के लक्ष्य और अन्य प्रभावों की कमी करने के पश्चात् व्यक्तियों को वेदित कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि विषय अधिकारी अपने विवेकासुसार विषय को, मूल्य के लिए अपने कारणों को लेखबद्ध करके, किसी निविष्टित दिन और समय तक मूल्य की कर सकेगा जहां विषय को 7 दिन अधिक अवधि के लिए इस प्रकार

मूल्य की किया जाता है, वहां जब तक कि निर्णीत ऋणी उसे अधिग्रहण करने की सम्मति नहीं देता है खण्ड (घ) के अधीन एक नए उद्घोषणा की जाएगी।

(ट) संपत्ति के लिए निम्न के समर, या उनके पश्चात् पश्चात्नीय जो विषय करने वाला अधिकारी नियत करेगा, नकद रूप में संदाय किया जाएगा और वेता को संपत्ति के किसी भाग को ले जाने की तब तक अनुज्ञा नहीं दी जाएगी जब तक कि वह उसके लिए पूर्णतः संदाय नहीं कर देता। जहां वेता प्रयत्न का संदाय नहीं कर पाता वहां संपत्ति का पुनः विषय किया जाएगा।

(ड) जहां किसी ऐसी, संपत्ति को, जिसे इन नियमों के अधीन कुर्क की गई है, किसी व्यक्ति द्वारा बलपूर्वक या छुपे मोर पर हटा लिया गया है, वहां विषय अधिकारी ऐसी संपत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए अधिकारिता वाली किसी सिविल न्यायालय को आवेदन कर सकेगा। जहां न्यायालय का आवेदन में अधि-वहित तथ्यों की मध्यमा के बारे में समाधान हो जाता है, वहां वह, ऐसी संपत्ति को, विषय अधिकारी की प्रत्यावेदित करने के लिए न्यायालय आवेदन कर सकेगा।

(ध) जहां, विषय के लिए नियत दिन से पूर्व, व्यक्तियुक्त या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या कुर्क की गई संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, संपूर्ण देय राशि, जिसमें अंतर्गत ब्याज, बढ़ा और संपत्ति को कुर्क करने में उपगत अन्य लागत भी है, संभाल कर देता है वहां विषय अधिकारी कुर्क का आवेदन रद्द कर देगा और संपत्ति को तत्काल निर्मुक्त कर देगा।

(ढ) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 60 के परंतुक में कुर्क से छूट प्राप्त वर्णित जंगम संपत्ति, इन नियमों के अधीन कुर्क या विषय के लिए दायी नहीं होगी।

(६) जहां, कुर्क की जाने वाली जंगम संपत्ति, किसी लोक सेवक या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी फर्म या किसी कंपनी के किसी सेवक का संबलम् या भत्ता या मजदूरी है, वहां वसूली अधिकारी, विषय अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, यह आदेश कर सकेगा कि रकम को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे संबलम् या भत्तों या मजदूरियों से या तो एक भुगतान में या मासिक किस्तों में, जैसा वसूली अधिकारी निदेश दे, रोक लिया जाए और आदेश के प्राप्त होने पर अधिकारी या ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसकी ड्यूटी ऐसे संबलम् या भत्ते या मजदूरी का संवितरित करने की है, रोक लगा और यथास्थिति आदेश के अधीन देय राशि को या मासिक किस्त को विषय अधिकारी को भेज देगा।

(7) (i) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति में व्यक्तिगत और अ-य की जंगम संपत्ति में सह-स्वामियों के रूप में उसका अंश या हित है वहां कुर्क, व्यक्तियों को अपने अंश या हित का अंतरण करने से या उस पर किसी भी प्रकार से भारित करने से प्रतिषिद्ध करने हुए, सूचना देकर की जाएगी।

(ii) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति, परक्राम्य भिन्न है, किसी न्यायालय में जमा नहीं है, न ही किसी लोक अधिकारी की अधिग्रहण में है, वहां कुर्क बाम्बिक अधिग्रहण द्वारा की जाएगी और विषय को कुर्क का आदेश करने वाले वसूली अधिकारी के कार्यालय में लाया जाएगा और उसके अग्रिम आदेश के अधीन रहते हुए, धारित किया जाएगा।

(iii) जहां कुर्क की जाने वाली संपत्ति, किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अधिग्रहण में है, वहां कुर्क ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुमति करने हुए की जाएगी कि ऐसी संपत्ति और कोई हित या उस पर संदेय होने वाला सामांश, सूचना जारी करने वाले वसूली अधिकारी के अग्रिम आदेश के अधीन रहते हुए, धारित किया जाए।

परन्तु जहाँ ऐसी संपत्ति किसी न्यायालय या अन्य अंग के बसूली अधिकारी की अधिरक्षा में है, वहाँ एक या अधिक और किसी मयन-रणन, कुर्की के आधार पर या अन्यथा ऐसी संपत्ति में, हितवन्त का दावा करने वाले ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बीच, जो व्यक्तिगत तौर पर, उद्भूत होने वाली पूंजीकता के किसी प्रण के अधिनियम के अधिनियम या बसूली अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

3. (i) जहाँ कुर्की की जाने वाली संपत्ति धन के संदाय के लिए या किसी बंधक या भार के प्रत्यक्ष में विधाय के लिए कोई डिपॉजिट है, वहाँ कुर्की, यदि कुर्की की जाने वाली डिपॉजिट किसी केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिस विषय को धारा 76 के अधीन केन्द्रीय रजिस्ट्रार द्वारा धारित किया था, धारित की गई थी, तो केन्द्रीय रजिस्ट्रार के आदेश द्वारा की जाएगी।

(ii) जहाँ केन्द्रीय रजिस्ट्रार, खंड (ख) के अधीन कोई आदेश करता है, वहाँ वह, ऐसे डिपॉजिट के आवेदन पर, निम्ने डिपॉजिट की है, कुर्की की गई डिपॉजिट के निष्पादन की कार्यवाही करेगा और शुरु प्रथम को, निष्पादित किए जाने के लिए, डिपॉजिट की संतुष्टि के लिए, उपयोग करेगा।

(iii) खंड (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की अन्य डिपॉजिट की कुर्की द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए, डिपॉजिट की के धारक को, कुर्की की गई डिपॉजिट के धारक का प्रतिनिधि समझा जाएगा, और वह उसके धारक के लिए किसी भी रीति में ऐसी कुर्की की गई डिपॉजिट का निष्पादन करने का हकदार होगा।

(iv) जहाँ किसी डिपॉजिट के निष्पादन में कुर्की की जाने वाली डिपॉजिट, खंड (1) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की डिपॉजिट से भिन्न कोई डिपॉजिट है, वहाँ कुर्की, बसूली अधिकारी द्वारा, ऐसी डिपॉजिट के धारक को, उसे किसी भी प्रकार में धारण करने या धारित करने से प्रतिषेध करने हुए, एक सूचना जारी करके, की जाएगी।

(v) इस उपनियम के अधीन कुर्की की गई किसी डिपॉजिट का धारक डिपॉजिट का निष्पादन करने वाला बसूली अधिकारी को, ऐसी जानकारी और सहायता देगा, जो युक्तियुक्त रूप से अपेक्षित हो।

(vi) अन्य डिपॉजिट की कुर्की द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए, डिपॉजिट किसी डिपॉजिट के धारक के आदेश पर, इस उपनियम के अधीन कुर्की का आदेश करने वाला बसूली अधिकारी, कुर्की की गई डिपॉजिट द्वारा आदेश निर्णीत श्रेणी को ऐसे आदेश की सूचना देगा; और उसकी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् ऐसे आदेश के उल्लंघन में निर्णीत श्रेणी द्वारा कुर्की की गई डिपॉजिट संबंधी किसी संदाय या समायोजन को उक्त बसूली अधिकारी की मार्फत या अन्यथा जब तक कुर्की प्रवृत्त रहती है, मान्यता नहीं दी जाएगी।

(9) जहाँ कुर्की की जाने वाली जंगम संपत्ति:—

(क) प्रत्यक्ष व्यक्तिगत को शोध कोई श्रेणी है,

(ख) किसी नियम की पंती में शेर या उसमें विनिर्दिष्ट कोई विशेष है, या

(ग) ऐसी अन्य जंगम संपत्ति है, जो व्यक्तिगत के कब्जे में नहीं है, उस संपत्ति से भिन्न, जो किसी सिविल न्यायालय में जमा है या उसकी अधिरक्षा में है वहाँ कुर्की —

(i) किसी श्रेणी की दशा में, लेनदार को श्रेणी बसूली करने से और श्रेणी को, उसका संदाय करने से;

(ii) किसी शेर या विशेष की दशा में, उस व्यक्ति को, जिसके नाम में शेर या विशेष है, शेर या विशेष को धारित करने से या उस पर कोई लापता या आग्रह प्राप्त करने से; और

(iii) किसी जंगम जंगम संपत्ति की दशा में, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में यह है, व्यक्तिगत को वापस देने से, प्रतिषेध करने हुए, बसूली अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विनिर्दिष्ट आदेश द्वारा की जाएगी।

ऐसे आदेश की एक प्रति, श्रेणी की दशा में, श्रेणी को, शेर या विशेष की दशा में, नियम के सम्बन्धित अधिकारी को और अन्य जंगम संपत्ति की दशा में, उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, भेजी जाएगी।

खंड (क) में विनिर्दिष्ट श्रेणी या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट विशेष जहाँ ही परिपक्व होता है, बसूली अधिकारी, संबंधित व्यक्ति को रकम का उसे संदाय करने का निर्देश देगा। जहाँ शेर या प्रत्याहरीय नहीं है, वहाँ बसूली अधिकारी, किसी दस्तावेज की मार्फत उसका विक्रय करने का प्रबंध करेगा। जहाँ शेर या प्रत्याहरीय है, वहाँ उसके मूल्य को बसूली अधिकारी, या खंड (ग) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को संदत्त किया जाएगा। खंड (ग) के उपखंड (iii) में विनिर्दिष्ट अन्य जंगम संपत्ति की दशा में संबंधित व्यक्ति को, जब वह व्यक्तिगत को परिपक्व हो जाती है, बसूली अधिकारी को सौंप देगा।

(10) स्थावर संपत्ति को, जब तक कि शेर को पहले ही कुर्की न किया गया हो, किसी डिपॉजिट के निष्पादन में विक्रय नहीं किया जाएगा परन्तु जहाँ डिपॉजिट, ऐसी संपत्ति के धारक के आधार पर प्राप्त की गई है, वहाँ उसे कुर्की करना आवश्यक नहीं होगा।

(11) कुर्की और विक्रय या स्थावर संपत्ति की कुर्की के बिना विक्रय में, निम्नलिखित नियम का अनुपालन किया जाएगा:

(क) उपनियम (2) के अधीन प्रस्तुत आवेदन में, उन स्थावर संपत्ति का, जिसके विरुद्ध कार्यवाही होगी, उतना वर्णन होगा जितना उसकी पहचान के लिए पर्याप्त हो और यदि ऐसी संपत्ति की पहचान संभावित या बंदोबस्त या सर्वेक्षण अभिलेख में संख्याओं द्वारा की जा सकती है, तो ऐसी संभावित या संख्याओं का विनिर्देश और डिपॉजिट के सर्वोत्तम विवरण के अनुसार और जहाँ तक वह उसे सुनिश्चित कर सके, व्यक्तिगत के ऐसी संपत्ति में शेर या हिन का विनिर्देश होगा।

(ख) उपनियम (3) के अधीन बसूली अधिकारी द्वारा जारी की गई मांग सूचना में व्यक्तिगत का नाम, वेय रकम, जिसमें खर्च यदि कोई है सम्मिलित है, और मांग सूचना तामोल करने वाले व्यक्ति को संदाय भुगतान, संदाय के लिए अनुज्ञात समय और संदाय न किए जाने की दशा में, कुर्की की और विक्रय की जाने वाली या कुर्की के बिना विक्रय की जाने वाली सम्पत्तियों के विनिर्देशों होंगी। मांग-सूचना प्राप्त होने पर, विक्रय अधिकारी, मांग-सूचना की एक प्रति व्यक्तिगत को या उसके कुटुम्ब के किसी, उसके पुरुष को उसके प्रायिक निवास-स्थान पर, या उसके प्राधिकृत अधिकारी को तामोल करेगा या कर-वापस या, यदि ऐसा वैयक्तिक तामोल संभव नहीं है, तो उसकी एक प्रति, यथास्थिति, कुर्की और विक्रय की जाने वाली या बिना कुर्की के विक्रय की जाने वाली स्थावर सम्पत्ति के किसी सहजदृश्य भाग पर सौंपी जाएगी:

परन्तु जहाँ बसूली अधिकारी का यह समायोजन हो जाता है कि व्यक्तिगत अपने विरुद्ध पल रही निष्पादन कार्यवाही को विफल करने या उसमें विघ्न करने के आग्रह से अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्यय करने वाला है वहाँ उपनियम (3) के अधीन बसूली अधिकारी द्वारा

जहाँ की गई मौज-सूचना में व्यक्तिकमी को उसके द्वारा देय रकम के संदाय के लिए कोई समय अनुज्ञान नहीं किया जाएगा और व्यक्तिकमी को सम्पत्ति तत्काल कुर्की कर दी जाएगी।

- (ग) यदि व्यक्तिकमी, अनुज्ञान समय के भीतर, मौज-सूचना में विनि-विष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है, तो विक्रय अधिकारी, निष्पादन के लिए आवेदन में विनिश्चित स्थावर सम्पत्ति की, यथास्थिति, कुर्की और विक्रय करने या बिना कुर्की के विक्रय करने के लिए निम्नलिखित राति से कार्यवाही करेगा।
- (घ) जहाँ कुर्की विक्रय में पहले अपेक्षित है, वहाँ विक्रय अधिकारी, यदि समय हो, कुर्की का सूचना व्यक्तिकमी को वैयक्तिक रूप में नामोल करवाएगा। जहाँ वैयक्तिक नामोल संभव न हो, वहाँ सूचना व्यक्तिकमी के अंतिम ज्ञात निवास-स्थान, यदि कोई हो, के निवास गृहजद्वय भाग पर लगाई जाएगी। कुर्की के तथ्य को ऐसे सम्पत्ति के या उससे लगे किसी स्थान पर और ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर, जो वसूली अधिकारी विक्रय का सम्पत्ति प्रसार करने के लिए आवश्यक समझे, खोजी पिटवाकर या सङ्गित श्रम से भी उद्घोषित किया जाएगा। कुर्की की सूचना में यह उपर्युक्त होगा कि, जब तक कि उसमें वर्णित तारिख के भीतर, ब्याज और खर्च सहित देय रकम का संदाय नहीं कर दिया जाता, सम्पत्ति विक्रय के लिए रखी जाएगी। एक प्रति डिक्री के धारक को भेजी जाएगी। जहाँ विक्रय अधिकारी ऐसा निर्देश दे, वहाँ कुर्की को भारत के राजपत्र में लोक उद्घोषणा द्वारा भी अधिसूचित किया जाएगा।
- (ङ) विक्रय को उद्घोषणा, विक्रय के लिए नियत की गई तारिख कम से कम नौ दिन पहले, वसूली अधिकारी के कार्यालय में और तानुक कार्यालय में सूचना लगाकर और उस ग्राम में (विक्रय की तारिख के पहले लगाने दो दिन और विक्रय के प्रारंभ से पहले विक्रय की तारिख को) खोजी पिटवाकर भी प्रस्तुत की जाएगी। ऐसे उद्घोषणा, जहाँ कुर्की विक्रय से पहले अपेक्षित है वहाँ, कुर्की के पश्चात् की जाएगी। सूचना डिक्री के धारक और व्यक्तिकमी को भी दी जाएगी। उद्घोषणा में विक्रय का समय और स्थान बताया जाएगा और जहाँ तक संभव हो, निम्नलिखित क्रमपूर्वक और ठीक-ठक, विनिविष्ट होगा :—
- (i) विक्रय की जाने वाली सम्पत्ति,
  - (ii) कोई विल्लगम जिसके लिए सम्पत्ति सहायी है,
  - (iii) वसूली के लिए रकम जिसके विक्रय का आदेश दिया गया है,
  - (iv) ऐसे अन्य बात, जिनके विक्रय अधिकारी यह समझता है कि वह केना के लिए, सम्पत्ति का प्रकृति और मूल्य को समझने के लिए आवश्यक है।

- (च) जब डा नियमों के अंतर्गत कोई स्थावर सम्पत्ति का विक्रय किया जाता है तो विक्रय, सम्पत्ति पर पूर्व विन्मोचन यदि कोई हो के अधीन रहने हुए किया जाएगा। डिक्री के धारक जब आपन का रकम, जिसके लिए विक्रय किया जाता है, 100 रु० से अधिक है, तब, विक्रय किए जाने के लिए ईप्सित सम्पत्ति को कुर्की की तारिख कम से कम बारह वर्ष की अवधि के लिए या ऐसे मामलों में, जो उप-नियम (1) के परन्तु के अधीन आते हैं, निष्पादन के लिए आवेदन की तारिख से पहले, रजिस्ट्रेशन विभाग में विल्लगम प्रमाणपत्र विक्रय अधिकारी को, ऐसे समय के भीतर जो उसके द्वारा या वसूली अधिकारी द्वारा निरत किया जाएगा, देगा विल्लगम प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का समय,

यथास्थिति, विक्रय अधिकारी या वसूली अधिकारी के विचकानुसार बढ़ाया जा सकता है। विक्रय लोक नीलामी द्वारा सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को किया जाएगा।

परन्तु यह कि जहाँ प्रस्तावित कीमत असम्पत्ति रूप से कम प्रवेष्ट होता है या अन्य यथोचित कारण हैं, वहाँ विक्रय अधिकारी सबसे ऊँची बोली को स्वीकार करने से इकार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

परन्तु यह और कि वसूली अधिकारी या विक्रय अधिकारी स्वविकानुसार, स्थान के लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, विक्रय को किसी विनिविष्ट दिन और समय के लिए स्थगित कर सकेगा। जहाँ विक्रय 7 दिन से अधिक अवधि के लिए इस प्रकार स्थगित किया जाता है, वहाँ खण्ड (क) के अर्धन ए० नई उद्घोषणा की जाएगी, जब तक कि व्यक्तिकमी उसे अधित्यजन करने की सम्मति न दे दे। विक्रय, उस तारिख से, जिसको उद्घोषणा की सूचना वसूली अधिकारी के कार्यालय में लगाई गई थी, संगणित कम-से-कम तीस दिन की गमाप्ति के पश्चात् होगा। विक्रय का समय और स्थान वह ग्राम, जहाँ विक्रय की गई सम्पत्ति स्थित है या उससे लगा स्थान ऐसा प्रमुख लोक समागम का स्थान, जिसे वसूली अधिकारी नियत करे, होगा।

परन्तु यह भी ऐसे मामलों में जहाँ संबंधित अधिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण विल्लगम प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं है, वहाँ विल्लगम प्रमाणपत्र के स्थान पर ग्राम पटवारी से या उस तत्स्थानी अधिकारी से, जिसे ऐसे विल्लगम के संबंध में जानकारी है, एक शपथपत्र, जो रजिस्ट्रेशन विभाग से इस प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित होगा कि संबंधित अधिलेखों के नष्ट हो जाने के कारण विल्लगम प्रमाणपत्र प्रदान नहीं किया जा सकता है, स्वीकार किया जाएगा।

- (छ) केना द्वारा, स्थावर सम्पत्ति की कीमत के 15 प्रतिशत के बराबर की धनराशि, त्रय के समय, विक्रय अधिकारी के पास निक्षेप का जाएगी और ऐसे निक्षेप न किए जाने की दशा में, सम्पत्ति तत्काल पुन विक्रय कर दी जाएगी।

परन्तु यह कि, जहाँ डिक्री का धारक केना है और वह खण्ड (क) के अर्धन कय धन की मुजरा करने का हकदार है, वहाँ विक्रय अधिकारी इस खण्ड की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे देगा।

- (ज) कय धन का अवशेष और विक्रय प्रमाणपत्र के लिए साधारण स्टाव के लिए अपेक्षित रकम का, विक्रय की तारिख से पंद्रह दिन के भीतर संदाय किया जाएगा।

परन्तु यह कि, स्टाम्पों को लागत का संदाय करने के लिए समय, अच्छा और पर्याप्त कारणों के लिए, विक्रय की तारिख से नौ दिन तक, वसूली अधिकारी के विचकानुसार बढ़ाया जा सकेगा।

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन संदाय की जाने वाली रकम की संगणना करने में, केना की किसी ऐसे मुजरा का फायदा होगा जिसके लिए वह खण्ड (क) के अधीन हकदार हो।

- (झ) खण्ड (ज) में वर्णित अवधि के भीतर संदाय न देने की दशा में, निक्षेप, यदि वसूली अधिकारी ठीक समझे तो, विक्रय के खर्च को चुकाने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार को समपहुत हो जाएगी और व्यक्तिकमी केना, सम्पत्ति या राशि के किसी ऐसे भाग, जिसके लिए उसका दाव में विक्रय होगा, के सभी धायों को समपहुत करेगा।

(घ) खंड (ज) में बणित रकम का संवाय, ऐसे संवाय के लिए अनुज्ञात अवधि के भीतर न देने की दशा में, स्थावर सम्पत्ति का प्रत्येक पुनः विक्रय, विक्रय के लिए इसमें इसके पहले विहित की गई रीति से और अवधि के लिए एक नई उद्घोषणा जारी की जाने के पश्चात्, किया जाएगा;

(ट) जहाँ डिक्ली का धारक, सम्पत्ति को क्रय करता है, वहाँ क्रय धन और डिक्ली पर देय रकम एक-दूसरे के बिसद्व मुजरा को जाएगी और विक्रय अधिकारी तबनुसार डिक्ली की पूर्णतः या भागसे: पुष्टि करेगा।

12. जहाँ विक्रय के लिए नियत न रीति से पूर्व व्यक्तिक्रमी या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति या विक्रय के लिए, हिप्मिंत सम्पत्ति में किसी दिन का दावा करने वाला कोई व्यक्ति, शोधपूर्ण राशि, और ब्याज, मत्ता और सम्पत्ति को विक्रय करने में उपगत अन्य खर्च, जिसके अन्तर्गत कुर्की, यदि कोई हो, के खर्च भी हैं, का संवाय करता है, वहाँ विक्रय अधिकारी कुर्की के आदेश को, जमा सम्पत्ति कुर्की की गई है, रद्द करने के पश्चात्, सम्पत्ति को तत्काल निरुद्ध कर देगा।

13. (i) जहाँ स्थावर सम्पत्ति का विक्रय अधिकारी द्वारा विक्रय किया गया है, वहाँ ऐसा व्यक्ति, जिसका ऐसे विक्रय से पहले अजित हक के आधार पर, ऐसी सम्पत्ति पर स्वाभिरव है या वह उसमें हितबद्ध है, वसूली अधिकारी के पास निम्नलिखित राशि जमा करके, विक्रय अपास्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा :—

(क) क्रय धन के 5 प्रतिशत के बराबर राशि का क्रेता को संवाय; और

(ख) विक्रय की उद्घोषणा में विनिर्दिष्ट उस बकाया रकम, जिसकी वसूली के लिए, विक्रय का आदेश किया गया था और उस पर ब्याज तथा कुर्की, यदि कोई हो, और विक्रय के खर्च और ऐसी रकम पर देय अन्य खर्च, वह रकम घटाकर जो ऐसी उद्घोषणा की तारीख तक डिक्ली का धारक प्राप्त कर चुका हो, डिक्ली के धारक को संवाय।

(ii) यदि ऐसा निक्षेप और आवेदन विक्रय की तारीख से तीन दिन के भीतर किया जाता है तो वसूली अधिकारी विक्रय को अपास्त करने हुए अदेश पारित करेगा और क्रेता को क्रय धन का जहाँ तक उसका निक्षेप किया गया है अवैदक द्वारा निक्षिप्त 5 प्रतिशत सहित, प्रतिसंवाय करेगा :

परन्तु यदि इस उप-नियम के अधीन एक से अधिक व्यक्तियों ने निक्षेप और आवेदन किया है तो विक्रय को अपास्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी को किए प्रथम निक्षेपक के आवेदन को, स्वीकार किया जाएगा।

(iii) यदि किसी व्यक्ति ने स्थावर सम्पत्ति को अपास्त करने के लिए उप-नियम (14) के अधीन आवेदन किया है तो वह इस उपनियम के अधीन आवेदन करने का हकदार नहीं होगा।

14. (i) स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की तारीख से तीन दिन के भीतर किसी भी समय, डिक्ली का धारक या आस्थितियों के अनुपातिक वितरण में जेयर का हकदार कोई व्यक्ति या वह व्यक्ति जिसका हित विक्रय द्वारा प्रभावित हुआ है, विक्रय को उसे प्रकाशित करने या संश्लिप्त करने में हुई किसी तात्त्विक अनियमितता या भूल या कपट के आधार पर अपास्त करने के लिए वसूली अधिकारी को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु, किसी भी विक्रय को अनियमितता या कपट के आधार पर तब तक अपास्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वसूली अधिकारी का यह मतप्रधान नहीं हो जाता है कि ऐसी अनियमितता, भूल या कपट के कारण आवेदक को मारगाल क्षति हुई है।

(ii) यदि आवेदन मंजूर हो जाता है, तो वसूली अधिकारी, विक्रय को अपास्त कर देगा और फिर से विक्रय के लिए निषेध दे सकेगा।

(iii) यदि विक्रय की तारीख से तीन दिन की समाप्ति पर विक्रय को अपास्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया जाता है या यदि ऐसा आवेदन किया गया है और उसे नामंजूर कर दिया गया है, तो वसूली अधिकारी विक्रय की पुष्टि करने वाला आदेश करेगा :

परन्तु यह कि यदि उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि विक्रय को इस बात के होते हुए भी अपास्त कर दिया जाना चाहिए कि ऐसा कोई आवेदन, किसी ऐसे आवेदन में जो किया गया है और उसे नामंजूर कर दिया गया है, अधिकृत आधार से भ्रष्ट आधार पर नहीं गया है, तो वह, अपने कारणों को लेखबद्ध करके, विक्रय को अपास्त कर सकेगा।

(iv) जब कभी स्थावर सम्पत्ति के विक्रय की इस प्रकार पुष्टि नहीं की जाती है या उसे अपास्त नहीं किया जाता है, यथास्थिति, निक्षेप या क्रय धन क्रेता को वापस कर दिया जाएगा ;

(v) किसी ऐसे विक्रय की पुष्टि के पश्चात्, वसूली अधिकारी, क्रेता को, विक्रय का प्रमाणपत्र जिस पर तमक, मुद्रा और हस्ताक्षर होने, प्रदान करेगा और ऐसे प्रमाणपत्र में विक्रय की गई सम्पत्ति और क्रेता का नाम कथित होगा, तथा यह ऐसे सभी न्यायालयों और अधिकरणों में क्रय के तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगा, जहाँ उसे साबित करना आवश्यक हो और वसूली अधिकारी की मुद्रा या हस्ताक्षर को साबित करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि उस प्राधिकारी के पास जिसके समक्ष उसे प्रस्तुत किया गया है, उसकी असलीयत के विषय में संदेह का कारण न हो;

(vi) इस उप-नियम के अधीन किया गया आदेश व्यक्तिगत होगा और किसी बाध या अन्य विधिक कार्यवाहियों में प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।

15. जहाँ स्थावर सम्पत्ति के किसी विधिपूर्ण क्रेता का किसी ऐसे व्यक्ति (जो व्यक्तिक्रमी न हो) से भ्रष्ट किसी व्यक्ति द्वारा, सम्भावपूर्वक अपनी ओर से सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए विक्रय की गई स्थावर सम्पत्ति पर कब्जा प्राप्त करने से प्रतिरोध किया जाता है और उसे रोका जाता है वहाँ, सक्षम अधिकारिता वाला कोई न्यायालय, अवैदक किए जाने पर, और उप-नियम 14 द्वारा उपबधित विक्रय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर, ऐसे क्रेता को कब्जा दिलाने के प्रयोजन के लिए उचित आदेशिका उसी रीति से जारी करवाएगा मानो क्रय के गई स्थावर सम्पत्ति क्रेता को न्यायालय के विनिश्चय द्वारा डिक्ली की गई व।

16. यह विक्रय अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह सम्पूर्ण स्थावर सम्पत्ति या उसके किसी भाग को देय धन के उन्मोचन में क्रय कर दे :

परन्तु यथा साध्य, स्थावर सम्पत्ति के किसी खंड या भाग का उतना से अधिक विक्रय नहीं किया जाएगा जितना शोध्य रकम और ब्याज तथा कुर्की यदि कोई हो, और विक्रय के खर्च के उन्मोचन के लिए पर्याप्त हो ;

17. इस नियमों के अधीन सूचना तामील करने में या अन्य प्रक्रिय में नियोजित व्यक्ति ऐसी वरों से भत्ता के हकदार होंगे जो वसूली अधिकार समय-समय पर नियत करें।

18. जहाँ इस नियम के अधीन स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय या स्थावर सम्पत्ति की कुर्की और विक्रय या बिना कुर्की के विक्रय के सबध में तपगत खर्च और प्रचार उपनियम (1) के अधीन डिक्ली के धारक द्वारा निक्षिप्त खर्च की रकम से अधिक है वहाँ ऐसा अधिकार, यथास्थिति, विक्रय की गई सम्पत्ति के विक्रय आगम या व्यक्तिक्रमी द्वारा संदत्त धन में से घटा दिया जाएगा और अनिशेष डिक्ली के धारक को उपलब्ध कराया जाएगा।

19. वसूली के लिए शोध्य किसी ऐसे धन हेतु, जिसके लिए इस नियम के प्रथम आवेदन किया गया है संदाय करने वाला प्रत्येक व्यक्ति

उस रकम के लिए विक्रय अधिकारी या बसूली अधिकारी द्वारा उस निमित्त समझौता किया गया अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित रसीद का हकदार होगा, ऐसी रसीद में संशय करने वाले व्यक्ति का नाम और वह विषय-वस्तु, जिसकी बाबत संदाय किया गया है, कथित होगा।

(20) (क) जहाँ इस नियम के अधीन कुर्की की गई किसी सम्पत्ति के बारे में कोई दावा या कुर्की के बारे में कोई आक्षेप, इस आधार पर किया गया है कि ऐसी सम्पत्ति ऐसी कुर्की के दायित्वाधीन नहीं है, वहाँ विक्रय अधिकारी, दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और इसका गुणा-गुण के आधार पर निपटान करेगा :

परंतु ऐसा कोई अन्वेषण तब नहीं किया जाएगा जब विक्रय अधिकारी यह समझता है कि ऐसा दावा या आक्षेप दुष्ट है।

(ख) जहाँ ऐसी सम्पत्ति का जिससे दावा या आक्षेप संबंधित है, विक्रय के लिए विज्ञापन किया गया है, वहाँ विक्रय अधिकारी विक्रय को दावा या आक्षेप के अन्वेषण तक मूलतः कर सकेगा।

(ग) जहाँ कोई दावा या कोई आक्षेप किया जाता है, वहाँ वह पक्षकार, जिसके विरुद्ध कोई आदेश किया जाता है, ऐसा अधिकार, जो वह विषय द्रष्ट संपत्ति पर दावा करता है, स्थापित करने के लिए वाद संस्थित कर सकेगा किंतु ऐसे वाद, यदि कोई हों, के परिणाम के अंतर्गत रहते हुए आदेश निष्पाद्यक होगा।

(21) (1) कीमत में कोई कमी, जो उपनियम (2) के खंड (न) के अधीन किए गए किसी पुनर्विक्रय पर केता के व्यापकम के कारण सम्भूत हो, और ऐसे पुनर्विक्रय करने में सभी खर्च विक्रय अधिकारी द्वारा बसूली अधिकारी को प्रमाणित किए जाएंगे, और वे विक्री के धारक या व्यक्तिकर्मी के अनुरोध पर इस नियम के उपबंधों के अधीन व्यक्तिकर्मी केता से बसूल किए जा सकेंगे। ऐसी बसूली के अनुबंधों खर्च भी यदि कोई हों, व्यक्तिकर्मी केता वहन करेगा।

(2) जहाँ सम्पत्ति का विक्रय दूसरे विक्रय के समय पहले विक्रय की कीमत से ऊँची कीमत पर हो, वहाँ पहले विक्रय के समय व्यक्तिकर्मी केता का, कीमत के अंतर या बूटि पर कोई दावा नहीं होगा।

(22) जहाँ किसी डिफ़ॉ के निष्पादन में कोई संपत्ति कुर्की की गई है, किंतु डिफ़ॉ के धारक के व्यक्तिकर्मी के कारण, बसूली अधिकारी, निष्पादन के आवेदन पर आगे कार्यवाही करने में असमर्थ है, वहाँ वह आवेदन को खारिज कर देगा या किसी पर्याप्त कारण के लिए कार्यवाही को किसी भविष्यवर्ती तारीख तक स्थगित कर देगा। ऐसे आवेदन के खारिज किए जाने पर, कुर्की समाप्त हो जाएगी।

(23) जहाँ आस्तियों विक्रय अधिकारी द्वारा धारित है और ऐसी आस्तियों की प्राप्ति में गड़बड़े, उन्मा व्यक्तिकर्मी के विरुद्ध डिफ़ॉ के निष्पादन के लिए आवेदन के अनुरोध में, एक से अधिक डिफ़ॉ के धारक से मांग सूचना प्राप्त हुई है, और डिफ़ॉ के धारकों ने डिफ़ॉ की तुष्टि प्राप्त नहीं की है, वहाँ आस्तियाँ, खर्च या आपन की कटौती करने के पश्चात्, विक्रय अधिकारी द्वारा ऐसे सभी डिफ़ॉ के धारकों के बीच, मिलित प्राप्तिवा संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 73 में उपबंधित रीति से अनुपातिक रूप से वितरित की जाएगी।

(24) जहाँ डिफ़ॉ की पूर्ण रूप से तुष्टि होने में गड़बड़े है किसी व्यक्तिकर्मी को मृत्यु हो जाती है, वहाँ उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन मूलक के विधिक प्रतिनिधियों के विरुद्ध किया जा सकेगा, और तबुपरि इस नियम के सभी उपबंध, इस उपनियम में यथा अन्यथा उप-बंधित के सिवाय, ऐसे लागू होने मानो ऐसा विधिक प्रतिनिधि व्यक्तिकर्मी है। जहाँ डिफ़ॉ ऐसे विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध निष्पादित की जाता है, वहाँ वह मूलक के सम्पत्ति की उस मात्रा तक दायित्वाधीन होगा जो उसके पास आती है और जिसका सम्यक रूप में व्ययन नहीं किया गया है, और ऐसे दायित्व का अभिविषय करने के प्रयोजन के लिए, डिफ़ॉ को निष्पादित करने वाला असूली अधिकारी अभ्येक्षा में या डिफ़ॉ के

धारक के आवेदन पर ऐसे विधिक प्रतिनिधि को, ऐसे लेखों जो वह ठीक समझे, प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकेगा।

23. निबंध से पूर्व कुर्की करने की पद्धति (1) धारा 87 के अधीन संपत्ति को कुर्की नियम 22 में उपबंधित रीति से की जाएगी।

(2) जहाँ कोई दावा, उपनियम (1) के अधीन कुर्की की गई संपत्ति के संबंध में किया जाता है, वहाँ ऐसे दावे का अन्वेषण नियम 22 में विनिर्दिष्ट रीति से और प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(3) जहाँ उपनियम (1) के अधीन किसी संपत्ति को कुर्की के लिए कोई निदेश दिया जाता है, वहाँ बसूली अधिकारी, कुर्की को पश्चाद्गत किए जाने का आदेश उस वक्ता में देगा—

(क) जब संबंधित पक्षकार, कुर्की के खर्च के लिए प्रतिभूति के साथ अपेक्षित प्रतिभूति देता है; या

(ख) अब समापक, धारा 81 की उपधारा (2) से खंड (ख) के अधीन यह अवधारित करता है कि संबंधित पक्षकार ने कोई अभिव्यक्ति संदेय नहीं है; या

(ग) जब केन्द्रीय रजिस्ट्रार, धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश पारित करता है कि संबंधित पक्षकार को प्रतिकर के रूप में किसी धन के प्रति सदाय या संपत्ति के प्रत्यावर्तन या मासाहटी की आस्तियों के संबंध में किसी राशि के अभिव्यक्ति आवश्यकता नहीं है; या

(घ) जब धारा 76 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवाद का उस पक्षकार के विरुद्ध, जिसके अनुरोध पर कुर्की की गई थी, विनिश्चय किया गया है।

(4) उपधारा (1) के अधीन की गई कुर्की से उन व्यक्तियों के, जो ऐसी कार्यवाहियों में पक्षकार नहीं थे, जिनके संबंध में कुर्की की गई थी, कुर्की से पूर्व विद्यमान अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही कोई ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध डिफ़ॉ धारण करता है, जिसकी संपत्ति कुर्की की गई है, ऐसी डिफ़ॉ के निष्पादन में कुर्की के अधन संपत्ति के विक्रय के लिए आवेदन करने से वारित होगा।

(5) जहाँ सम्पत्ति इस नियम के उपबंधों के आधार पर कुर्की के अधीन है, और कोई डिफ़ॉ बाद में उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसकी संपत्ति कुर्की की गई है, पारित की गई है, वहाँ ऐसी डिफ़ॉ के निष्पादन के लिए किसी आवेदन पर, संपत्ति की पुनः कुर्की के लिए आवेदन करना आवश्यक नहीं होगा।

24. समन तामील की पद्धति—(1) अधिनियम या उन नियमों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक समन लिखित में होगा, उस अधिकारी जिनने यह जारी किया है, का मुद्रा, यदि कोई हो, द्वारा अधिप्रमाणित होगा और ऐसे अधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा। उसमें समन किए गए व्यक्ति से उस अधिकारी के समक्ष बताए गए समय और स्थान पर उपस्थित होने का अवेशा की जाएगी, और यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि, साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के प्रयोजन या दोनों प्रयोजनों के लिए, उनका उपस्थिति अपेक्षित है या नहीं और किसी विशिष्ट वक्ता के का, जिसे प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, समन में, व्यक्तिगत रूप से श्रुतता सहित विवरण दिया जाएगा।

(2) किसी व्यक्ति को, साक्ष्य देने के लिए समन किए बिना दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया जा सकेगा, और किसी ऐसे व्यक्ति, जिसे केवल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समन किया गया है, के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने समन का अनुपालन किया है, यदि वह ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के बजाय उसे प्रस्तुत करवाना है।

(3) अधिनियम या इन नियमों के अधीन किसी व्यक्ति पर समन की तामील निम्नलिखित किसी भी रीति से की जा सकती है:—

- (क) उसे उस व्यक्ति का देकर या निविदित करके; या
- (ख) यदि ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है, तो उसे उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर या कारबार के स्थान पर छोड़कर या उसे उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को देकर या निविदित करके; या
- (ग) यदि ऐसे व्यक्ति का पता केन्द्रीय रजिस्ट्रार या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति को ज्ञात है, तो उसे उस व्यक्ति को, रसीदी रजिस्ट्री-कृत डाक द्वारा भेजकर; या
- (घ) यदि पूर्वोक्त साधन में से कोई भी उपलब्ध न हो, तो उसे उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान या कारबार के स्थान के किसी सहज दृश्य भाग पर लगाकर।

(4) जहाँ तामील करने वाला अधिकारी, समन को एक प्रति, प्रतिवादी को या किसी अधिकारी का या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से परिवर्त या निविदित करना है, वहाँ उसने उस व्यक्ति के हस्ताक्षर जिसे प्रति इस प्रकार परिवर्त या निविदित की गई है, मूल समन पर, तामील की रसीद के रूप में पुष्ठांकित करने की अपेक्षा की जाएगी।

(5) तामील करने वाला अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में, जिनमें उपनियम (4) के अन्तर्गत समन तामील किए गए हैं, मूल समन पर या उससे एक विवरणी, वह समय जब वह रीति जिसे और उस व्यक्ति को जिसे तामील किया गया पड़चानने वाले तथा समन के परिवर्तन या निविदान के लिए माफ़ी होने वाले व्यक्ति, यदि कोई हो, का नाम और पता, कथित करते हुए पुष्ठांकित या उपाबद्ध करेगा या पुष्ठांकित या उपाबद्ध करवाएगा।

(6) जहाँ समन किए जाने वाला प्रतिवादी लोक अधिकारी या किसी कंपनी का सेवक या स्थानीय प्राधिकारी है, वहाँ समन जारी करने वाला अधिकारी, यदि वह प्रतीत होता है कि समन इस प्रकार भ्रष्टाचारपूर्वक तामील किए जा सकेंगे, तो उसे समन किए जाने वाले पक्षकार, को तामील करने के लिए उस कार्यालय के प्रधान को जिसमें वह नियोजित है, प्रतिवादी द्वारा रसीद जाने वाली प्रति के साथ, रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेज सकेगा।

#### अध्याय—6

ऐसी सोसाइटियां, जो राज्यों के पुनः संगठन के परिणामस्वरूप बहुराज्य सहकारी सोसाइटियां बन गई हैं

25. बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों के पुनर्गठन या पुनः संगठन के लिये स्कीम तैयार करना।

(1) केन्द्रीय रजिस्ट्रार या कोई प्राधिकृत अधिकारी, धारा 95 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राज्यों के पुनः संगठन के परिणामस्वरूप, इस प्रकार किये गये किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पुनर्गठन या पुनः संगठन के लिये धारा 95 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट, एक स्कीम तैयार करेगा, और स्कीम की एक प्रति बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष या समापति को इस निदेश के साथ अग्रहित करेगा कि स्कीम को, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के इस प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बसाई गई साधारण निकाय की बैठक में रखा जाये।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट बैठक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सदस्यों और लेनदारों को, उपनियम (3) में निर्दिष्ट रीति से जारी की गई सूचना की तारीख से कम से कम 40 दिन पश्चात् बुलाई जायेगी।

(3) प्रत्येक सदस्य को, एक लिखित सूचना, जिसमें बैठक की तारीख, समय और स्थान तथा वहाँ पर किये जाने वाले कारबार

बिनिदिष्ट होगा, दी जायेगी और उसके साथ, बैठक में विश्वास किए जाने वाली स्कीम की एक प्रति होगी। प्रत्येक सदस्य और लेनदार को सूचना—

- (i) व्यक्तिगत रूप से परिवर्त या निविदित की जायेगी;
- (ii) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी; या
- (iii) किसी ऐसी अन्य रीति से, जैसी सोसाइटी की उपविधियों में विनिविष्ट की जाये, तामील की जायेगी।

(4) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का शासित करने वाले किसी नियम या उपनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के विरुद्ध होने हुए भी, जहाँ केन्द्रीय रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी का इस निमित्त समाधान हो जाता है कि, सोसाइटी का अध्यक्ष या समापति उपनियम (1) की अपेक्षानुसार विशेष बैठक बुलाने में असफल हो गया है, वहाँ, यथास्थिति, केन्द्रीय रजिस्ट्रार या प्राधिकृत अधिकारी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय की बैठक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के सभी सदस्यों और लेनदारों को 14 दिन की सूचना देकर बुलाएगा।

#### अध्याय—7

##### परीक्षण

26. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी का पता

प्रत्येक बहुराज्य सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में सोसाइटी का पता होगा, जिस पर सभी सूचनायें और संसूचनायें भेजी जा सकें। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पते में, राज्य जिला, डाकखाना और ग्राम या नगर का नाम सम्मिलित होगा। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के पते में कोई परिवर्तन केन्द्रीय रजिस्ट्रार को, ऐसे परिवर्तन के एक मास के भीतर संसूचित किया जायेगा।

27. निरसन और व्यावृत्ति

(1) बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी नियम, 1958 को निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, ऐसे निरसित किसी नियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई, जब तक कि ऐसी कोई बात या कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो, इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

[म० एन-11012/1/84-एल एण्ड एम]

क० एन० अध्यक्षारीकरण, अपर सचिव

#### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

New Delhi, the 28th October, 1985

Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985.

GSR 812(E).—In exercise of the powers conferred by section 109 of the Multi-State Co-operative

Societies Act, 1984 (51 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

## CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title and extent.— (1) These rules may be called the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definition:—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (i) "Act" means the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984);
- (ii) "authorised officer" means an officer authorised by the Central Government for the purposes of section 95;
- (iii) "decree" means any decree of a civil court and includes any decision or order referred to in section 85;
- (iv) "decree holder" means any person holding a decree as defined in clause (iii);
- (v) "defaulter" means any multi-State co-operative society, any co-operative society, member or any other person committing default;
- (vi) "Form" means a Form appended to these rules;
- (vii) "general meeting" means a meeting of the general body including a representative general body referred to in section 29;
- (viii) "judgement debtor" means any multi-State co-operative society against which or any person against whom a decree has been obtained;
- (ix) "Recovery Officer" means any person authorised to exercise the powers of the Central Registrar under section 85;
- (x) "Sale Officer" means a person authorised by the Central Registrar, by general or special order, to attach and sell the property of judgement-debtor or to execute any decree by attachment and sale of property;
- (xi) "section" means a section of the Act;
- (xii) words and expressions defined in the Act and used but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

## CHAPTER II

### PRIVILEGES, PROPERTIES AND FUNDS OF MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES

3. Certifying copies of entries in books.—(1) For the purposes specified in sub-section (1) of section 56, a copy of any entry in a book of a multi-State co-operative society regularly kept in the course of its business shall be certified—

- (i) by the Chief Executive of the society or any other member or employee authorised by the bye-laws of the society;
- (ii) where an order has been passed under section 48 superseding the board and appointing an administrator, by the administrator or any other officer authorised by him; and
- (iii) where an order has been passed under sub-section (1) of section 80 appointing a liquidator of the multi-State co-operative society, by the liquidator.

(2) Every certified copy shall bear the seal of the multi-State co-operative society.

4. Contribution towards co-operative education fund.—(1) Every multi-State co-operative society shall credit a sum calculated at one per cent of its net profits every year as contribution to the co-operative Education fund maintained by the National Co-operative Union of India Limited, New Delhi. The co-operative education fund shall be administered by a committee nominated for that purpose consisting of the following members:—

- (i) The President of the National Co-operative Union of India Limited, New Delhi Chairman
- (ii) The Central Registrar Member
- (iii) The Financial Adviser to the Department of Agriculture & Co-operation in the Ministry of Agriculture Member
- (iv) Two representatives of the multi-State co-operative societies to be nominated by the Central Government for every two years Members
- (v) The Director General National Council for Co-operative Training, New Delhi Member
- (vi) The Director, Vaikunth Mehta National Institute of Co-operative Management, Pune Member

(2) The co-operative education fund shall be utilised for the purposes connected with the education of members and human resource development for co-operatives.

5. Disposal of net profits.—The net profits of every multi-State co-operative society shall be disbursed or utilised subject to the following terms and conditions:—

- (a) No dividend shall be declared or paid except from out of the net profits and shall not exceed 12 per cent per annum on the paid-up share capital.
- (b) No dividend shall be declared or paid while a claim due from the multi-State co-operative society to a depositor or lender remains unsatisfied.
- (c) No donation made by the multi-State co-operative society out of the net profits of any year shall exceed rupees five lakhs.

6. Investment of funds.—A multi-State co-operative society may invest or deposit its funds in any one or more of the following modes:—

- (i) any mode provided in clauses (a) to (c) of section 62;
- (ii) any post office savings bank;
- (iii) any savings scheme launched by the Central or the State Government;
- (iv) the shares of a corporation or other body corporate in which the Central or the State Government or both hold more than fifty per cent of the shares; and
- (v) the debentures floated by a corporation or a body corporate if such debentures are guaranteed by the Central or the State Government or by the Reserve Bank of India.

7. Objects and investments of reserve fund.—

(1) Every multi-State co-operative society shall maintain a reserve fund to meet any one or more of the following objects:—

- (i) unforeseen losses;
- (ii) claim of the creditors of the society which cannot be otherwise met; and
- (iii) such other financial needs in times of special scarcity.

(2) Every multi-State co-operative society may, with the permission of the Central Registrar invest or deposit its reserve fund in:—

- (i) acquisition or purchase of land and building and construction of building for—
  - (a) its office, staff and equipment
  - (b) installation or operation of its machinery or plant;
- (ii) purchase of machinery or plant which is required for its main business;

(iii) acquisition or purchase of land and building and construction of buildings for the purposes mentioned in clause (i) (a) and also for the benefit of its members in accordance with the provisions of its bye-laws; and

(iv) its own business.

(3) The reserve fund of a multi-State co-operative society shall be indivisible and no member shall have any claim or a share in it.

(4) No multi-State co-operative society whose reserve fund has been separately invested or deposited shall draw upon, pledge or otherwise employ such fund except with the sanction of the Central Registrar previously obtained.

(5) The utilisation of the reserve fund for the objects mentioned in sub-rule (1) shall be subject to the condition that any amount drawn shall be reimbursed from the profits accruing in subsequent co-operative year or years as directed by the Central Registrar. The Central Registrar may, however, having regard to the special circumstances of the society, permit that the reserve fund drawn and utilised for the objects mentioned under clauses (ii) and (iii) of sub-rule (1) may not be reimbursed wholly or partially as he may direct.

(6) (a) In the case of winding up of a multi-State co-operative society, the reserve fund and the other funds of the multi-State co-operative society shall be applied first in discharge of the liabilities of the multi-State co-operative society in accordance with the priority specified in items (i) to (vi) below:—

- (i) salary and wages or other payments, if any, due to the employees of the multi-State co-operative society;
- (ii) security deposits of staff, if any;
- (iii) borrowings held from Government or on the guarantee of Government, if any;
- (iv) deposits of non-members, if any;
- (v) loans, if any; and
- (vi) deposits of members, if any.

(b) The balance, if any, after discharging the liabilities mentioned in clause (a) shall be applied to the re-payment of the paid-up share capital and thereafter to the payment of dividend where it has not been paid.

(c) Notwithstanding anything contained in clause (b), no dividend shall be paid if the bye-laws of the multi-State co-operative society do not provide for payment of dividend.

(7) Any surplus remaining after payments mentioned in sub-rule (6) shall be applied by the liquidator, after consulting members, for contribution

to National Defence Fund or to co-operative education fund referred to in rule 4 or to any other charitable purpose or local objects of public utility subject to the approval of the Central Registrar.

8. Writing off of bad debts and losses.—All loans including interest thereon and recovery charges in respect thereof which are found irrecoverable and are certified as bad debts, by the auditor appointed under section 67, shall first be written off against the Bad Debt Fund and the balance, if any, may be written off against the Reserve Fund and the share capital of the multi-State co-operative society.

All other dues and accumulated losses or any other loss sustained by the multi-State co-operative society which cannot be recovered and have been certified as irrecoverable by the auditor may be written off against the Reserve Fund of the multi-State co-operative society;

Provided that—

- (a) no bad debts or losses shall be written off without the sanction of the general body;
- (b) before any such bad debts or losses are written off, the multi-State co-operative society shall obtain the approval of the Central Registrar.

Provided further that the Central Registrar may, while giving the approval, impose such conditions as to the recoupment of the Bad Debt Fund and restoration of part or whole of the amount written off against the Reserve Fund, from out of future profits as he deems fit.

9. Transactions with non-members.—Save as otherwise provided for in section 65 and except with the general or special sanction of the Central Registrar, no multi-State co-operative society shall enter into any credit transaction with a person other than a member, unless the by-laws of the multi-State co-operative society permit it to enter into such transactions.

10. Application for loan:—(1) An application for loan shall be in such form as may be required by the board of the multi-State co-operative society and shall state the purpose for which the loan is required in the manner laid down in the bye-laws of the society.

(2) For every loan, a member shall furnish such security as may be required under the bye-laws of the multi-State co-operative society.

(3) The period of repayment of the loan shall be as may be provided in the bye-laws, but in no case exceed five years.

(4) In any multi-State co-operative society in which the liability of the members is limited by shares, no loan shall be granted to a member exceeding ten times the amount of share capital paid by him or as may be laid down in the bye-laws.

11. Contributory provident fund:—(1) Every multi-State co-operative society which has in its service 5 or more regular employees shall establish a Contributory Provident Fund referred to in subsection (1) of section 66.

(2) The multi-State co-operative society creating such a fund shall provide for the following in its bye-laws:—

- (a) Authority to administer the fund.
- (b) Amount of contribution to be deducted from the employee's salary.
- (c) Mode of nomination for payment of the amount of the contributory provident fund in case of employee's death.
- (d) Purpose for which, the extent to which, and the period after which, advances may be made against the security of such fund and the number of monthly instalments in which advance is to be repaid.
- (e) Refund of employees' contribution and contribution made by the society.
- (f) Maintenance of accounts of such fund.

(3) The amount of contribution that can be deducted from the salary of an employee of the multi-State co-operative society shall not be less than 8.33 per centum of his basic salary.

(4) The multi-State co-operative society may make such contribution every year to the employees' contributory provident fund as may be approved by the board. Such contribution shall not exceed 8.33 per centum of the basic salary of the employee.

12. Restriction on borrowings of limited liability of multi-State co-operative society:—

No multi-State co-operative society with limited liability shall accept deposits or loans, or by any other way incur liability exceeding 10 times the sum of the paid-up share capital plus accumulated reserves minus any losses.

Provided that the Central Registrar, for reasons to be recorded in writing, may permit a multi-State co-operative society to incur liabilities exceeding the aforesaid limit.

### 13. Maintenance of liquid resources and distribution of assets:—

Every multi-State co-operative society which obtains any portion of its working capital by deposits, shall,—

- (a) maintain such liquid resources and in such form as may be specified by the Reserve Bank of India in the case of those multi-State co-operative credit societies which are coming under the purview of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) and by the Central Registrar in the case of other multi-State co-operative societies; and
- (b) utilise only such portion of its working capital in lending business and distribute its assets in accordance with such standards as may be specified from time to time by the Central Registrar.

14. Shares not to be hypothecated to the multi-State co-operative society:—The shares of a multi-State co-operative society shall not be hypothecated to that society by its members as security for a loan.

15. Loan on security of non-members:—No multi-State co-operative society shall make any loan to a member on a security bond given by a non-member:

Provided that the Central Registrar may for reasons, to be recorded in writing, exempt any multi-State co-operative society or class of multi-State co-operative societies from the operation of this rule.

## CHAPTER III

### AUDIT AND ACCOUNTS

16. Books of Accounts.—Every multi-State co-operative society shall keep books of account with respect to—

- (a) all sums of money received and expended and the matters in respect of which the receipt and expenditure take place;
- (b) all sales and purchase of goods;
- (c) the assets and liabilities;
- (d) in the case of a multi-State cooperative society engaged in production, processing and manufacturing, particulars relating to utilisation of materials or labour or other items of costs as may be specified by the Central Registrar.

17. Subject matter of audit:—(1) The audit of a multi-State co-operative society under sub-section (1) of section 67 shall include, in addition to the mat-

ters specified in sub-section (2) of that section, the following particulars:—

- (a) Whether the auditor has obtained all the information and explanations which, to the best of his knowledge and belief, are necessary for the purposes of his audit;
- (b) Whether in his opinion proper books of accounts as specified in these rules and bye-laws have been kept by the multi-State co-operative society so far as it appears from the examination of those books and proper returns adequate for the purposes of his audit have been received from the branches not visited by him.
- (c) Whether the balance-sheet and profit and loss account exhibit a true and fair view of the state of affairs of the multi-State Cooperative society according to best of his information and explanations given to him and as shown by the books of the multi-State co-operative society; and
- (d) Whether there has been any material impropriety or irregularity in the expenditure or in the realisation of money due to the multi-State Co-operative Society.

(2) Where in any of the matters referred to in sub-rule (1) the answer is in the negative or in the affirmative with any remark, the auditor shall give reasons for such answer with facts and figures in support of such remarks.

(3) The audit report shall also contain schedules with particulars of:—

- (a) all transactions which appear to be contrary to the provisions of the Act, the rules or the bye-laws of the multi-State co-operative society.
- (b) Any money belonging to the multi-State co-operative society which appears to the auditor to be bad or doubtful of recovery.
- (c) The loans given by the multi-State co-operative society to the members of the board; and
- (d) any other matter as may be specified by the Central Registrar in this regard.

(4) The auditor shall make his report to the multi-State co-operative society and also send a copy of that report direct to the Central Registrar.

The Central Registrar may for reasons to be recorded in writing, direct that if any portion of the audit report which appears to him of objectionable nature or not justified, be expunged and the portion so expunged shall not form part of the audit report.

(5) The audit report given by the auditors shall be considered by the board of a multi-State co-operative society and placed before the general body with their comments.

(6) The defects pointed out by the auditors in the working of the multi-State cooperative society shall be specifically considered by the board and a compliance report explaining the measures taken to rectify the defects be submitted to the Central Registrar within three months of the receipt of the audit report.

#### CHAPTER IV

#### WINDING UP OF MULTI-STATE COOPERATIVE SOCIETIES

##### 19. Procedure to be adopted by liquidator:—

Where a liquidator has been appointed under sub-section (1) of section 80 the following procedure shall be adopted:—

- (a) The appointment of the liquidator shall be notified by the Central Registrar in the Official Gazette.
- (b) The liquidator shall, as soon as the order of winding up of the multi-State co-operative society takes effect, publish by such means as he may, think proper, a notice, requiring all claims against the multi-State co-operative society, the winding up of which has been ordered, to be submitted to him within two months of the publication of the notice. All liabilities recorded in the account books of a multi-State co-operative society shall be deemed ipso-facto to have been duly submitted to him under this clause.
- (c) The liquidator shall investigate all the claims against the multi-State Co-operative Society and decide questions of priority arising between claimants.
- (d) The liquidator shall recover all sums and other properties to which the multi-State cooperative society is entitled and may institute such suits for that purpose or such suits incidental to liquidation proceedings as he may think proper.
- (e) The liquidator may empower any person, by general or special order in writing, to make collections and to grant valid receipts on his behalf.
- (f) The liquidator shall, after setting the assets and liabilities of multi-State cooperative society, as they stood on the date on which the order of winding up is made, proceed next to determine from time to time the contribution including debts due and costs of liquidation

to be made or remaining to be made by each of its members, past members, or by the estates, or nominees, heirs or legal representatives of deceased members or by any officers or former officers, to the assets of the multi-State co-operative society, under clause (b) of sub-section (2) of section 81. Should necessity arise, he may also make a subsidiary order regarding such contributions and such order shall be enforceable in the same manner as the original order.

- (g) All funds in the charge of the liquidator shall be deposited in the Post Office Savings Banks or in a co-operative bank or with such other banks as may be approved by the Central Registrar and shall stand in his name.
- (h) The Central Registrar shall fix the amount of remuneration, if any, to be paid to the liquidator. The remuneration shall be included in the cost of liquidation, which shall be payable out of the assets of the multi-State co-operative society in priority of all other claims.
- (i) The liquidator may call for the meeting of the members of the multi-State co-operative society under liquidation.
- (j) The liquidator shall submit to the Central Registrar a quarterly report in such form as the Central Registrar may, specify showing the progress made in liquidation of the multi-State co-operative society.
- (k) The liquidator shall keep such books and accounts as may from time to time be specified by the Central Registrar who may at any time cause such books and accounts to be audited.
- (l) At the conclusion of the liquidation, the liquidator shall call for a general meeting of the members of the dissolved society at which the liquidator or any other person authorised by him, by special or general order in writing in this behalf, shall summarise, the result of his proceedings and shall take a vote as to the disposal of any surplus funds. The Liquidator shall submit his final report to the Central Registrar with a copy of the proceedings of the general meeting referred to above and make over to the Central Registrar all books and registers and accounts etc., belonging to the multi-State co-operative society and all books and accounts relating to the liquidation proceeding kept by him.
- (m) If any liability cannot be discharged by the liquidator owing to the whereabouts of the claimants not being known or for any other cause, the amount covered by such undischarged liability may be deposited in a Co-operation Bank and shall be available for

meeting the claims of the person or persons concerned.

- (n) A liquidator may, at any time, be removed by the Central Registrar and he shall on such removal be bound to hand over all the property and documents relating to the society under liquidation to such persons as the Central Registrar may direct.
- (o) All the books and records of a multi-State Co-operative society whose registration has been cancelled and the proceedings of liquidation of a multi-State co-operative society ordered to be wound up may be destroyed by the Central Registrar after the expiry of three years from the date of the order cancelling the registration of the multi-State co-operative society.

20. Application of assets of the multi-State Co-operative society.—The assets of the multi-State co-operative society shall be applied in order of priority as given below for payment of the liabilities:—

- (1) Pro-rata payment of all outside liabilities.
- (2) Pro-rata repayment of loans and deposits of members.
- (3) Pro-rata refund of share capital.
- (4) Pro-rata payment of dividend on the share at the rate not exceeding 6.25 per cent per annum for the period of liquidation.

21. Disposal of surplus Assets.—For the purpose of sub-section (b) of section 82 the surplus assets shall be distributed among the members in proportion to the share capital held by the members or in proportion to the business done by the members with the multi-State co-operative society as may be determined by the Central Government before according sanction under sub-clause (b) of section 82.

## CHAPTER V

### EXECUTION OF DECREES, ORDERS AND DECISION

22. Procedure in execution of decrees, orders and decisions.

- (1) Any decree-holder requiring the provisions of clause (c) of section 85 to be applied, shall apply to the Recovery officer in whose jurisdiction the cause of action arose and shall deposit the necessary costs as fixed by the Central Registrar. If the judgement-debtor resides or the property to be proceeded against is situated outside the jurisdiction of such Recovery Officer, the Recovery Officer shall transfer the application to the Recovery Officer in whose jurisdiction the judgement-debtor resides or the property is situated.

(2) Every such application shall be made in the Form specified by the Central Registrar and shall be signed by the decree-holder. The decree-holder may indicate whether he wishes to proceed against the immovable property mortgaged to the decree-holder or other immovable property or to secure the attachment of movable property.

(3) On receipt of such application, the Recovery Officer shall verify the correctness and genuineness of the particulars set forth in the application with the records, if any, in the office of the Central Registrar and prepare a demand notice in writing in duplicate in the form specified by the Central Registrar, setting forth the name of the defaulter and the amount due and forward it to the Sale Officer.

(4) Unless the decree-holder has expressed a desire that proceedings should be taken in a particular order as laid down in sub-rule (2), execution shall ordinarily be taken in the following manner:—

- (i) movable property of the defaulter shall be first proceeded against, but this shall not preclude the immovable property being proceeded against simultaneously in case of necessity.
- (ii) if there is no movable property, or if the sale proceeds of the movable property, or properties attached and sold are insufficient to meet in full the demand of the decree-holder, the immovable property mortgaged to the decree-holder, or other immovable property belonging to the defaulter may be proceeded against.

(5) In the seizure and sale of movable property the following rules shall be observed:—

- (a) The Sale Officer, shall after giving previous notice to the decree-holder, proceed to the village or place where the defaulter resides or the property to be distrained is situated and serve a demand notice upon the defaulter if he is present. If the amount due together with the expenses be not at once paid, the Sale Officer shall make the distress and shall immediately deliver to the defaulter a list or inventory of the property distrained and an intimation of place and day and hour at which the distrained property will be brought to sale if the amounts due are not previously discharged. If the defaulter is absent, the Sale Officer shall serve the demand notice on some adult male member of his family, or on his authorised agent, or when such service cannot be effected, shall affix a copy of the demand notice on some

- conspicuous part of his residence. He shall then proceed to make the distress and shall fix the list of the property attached on the usual place of residence of the defaulter, endorsing thereon the place where the property may be lodged or kept and an intimation of the place, day and hour of sale.
- (b) After the distress is made, the Sale Officer may arrange for the custody of the property attached with the decree-holder or otherwise. If the Sale Officer requires the decree-holder to undertake the custody of the property he shall be bound to do so and any loss incurred owing to his negligence shall be made good by the decree-holder. If the attached property is live-stock, the decree-holder shall be responsible for providing the necessary food therefor. The sale Officer may, at the instance of the defaulter or of any person claiming an interest in such property, leave it in the village or place where it was attached, in the charge of such defaulter or person, if he entered into a bond in the form specified by the Central Registrar with one or more sufficient sureties for the production of the property when called for.
- (c) The distress shall be made after sunrise and before sunset and not at any other time.
- (d) The distress levied shall not be excessive, that is to say, the property distrained shall be as nearly as possible proportionate to the sum due by the defaulter together with interest and all expenses incidental to the distraint, detention and sale.
- (e) If crops or ungathered products of the land belonging to a defaulter are attached, the Sale Officer may cause them to be sold when fit for reaping or gathering, or at his option may cause them to be reaped for gathered in due season and stored in proper place until sold. In the latter case, the expense of reaping or gathering and storing such crops or products shall be defrayed by the owner upon his redeeming the property or from the proceeds of the sale in the event of its being sold.
- (f) The Sale Officer shall not work the bullocks or cattle, or make use of the goods or effect distrained; and he shall provide the necessary food for the cattle or livestock, the expense attending which shall be defrayed by the owner upon his redeeming the property or from the proceeds of the sale in the event of its being sold.
- (g) It shall be lawful for the Sale Officer to force open any stable, cow house, granary, godown, out-house or other building and he may also enter any dwelling house, the outer door of which may be open and may break open the door of any room in such dwelling house for the purpose of attaching property belonging to a defaulter and lodged therein, provided always that it shall not be lawful for the officer to break open or enter apartment in such dwelling house appropriated for the zenana or residence of women except as hereinafter provided.
- (h) Where the Sale Officer may have reason to suppose that the property of a defaulter is lodged within a dwelling house the outer door of which may be shut or within any apartments appropriated to women which by custom or usage are considered private, the sale Officer shall represent the fact to the officer in charge of the nearest police station. On such representation the officer-in-charge of the said station shall send a police officer to the spot in the presence of whom the Sale Officer may force open the other door of such dwelling house, in like manner as he may break open the door of any room within the house except the zenana. The Sale Officer may also, in the presence of a police officer, after due notice given for the removal of women within a zenana and, after furnishing means for their removal in a suitable manner if they be women of rank who, according to the custom of usage cannot appear in public, enter the zenana apartments for the purpose of distraining the defaulter's property, if any, deposited therein, but such property, if found, shall be immediately removed from such apartments after which they shall be left free to the former occupants.
- (i) The Sale Officer shall on the day previous to and on the day of sale cause proclamation of the time and place of the intended sale to be made by beat of drum in the village or place in which the defaulter resides on two consecutive days previous to the date of sale and on the day of sale prior to the commencement of the sale and in such other place or places as the officer may consider necessary to give due publicity to the sale. No sale shall take place until after the expiration of the period of 15 days from the date on which the sale notice has been served or affixed in the manner prescribed in clause (a):
- Provided that where the property seized is subject to speedy and natural decay, or

where the expense of keeping it in custody is likely to exceed its value, the Sale Officer may sell it at any time before the expiry of the said period of 15 days, unless the amount due is sooner paid.

- (j) At the appointed time the property shall be put up in one or more lots, as the Sale Officer may consider advisable, and shall be disposed of to the highest bidder :

Provided that it shall be open to the Sale Officer to decline to accept the highest bid where the price offered appears to be unduly low or for other reasons. Where the property is sold for more than the amount due, the excess amount after deducting the interest and the expenses of process and the other charges, shall be paid to the defaulter :

Provided, further, that the Sale Officer may, in his discretion, adjourn the sale to a specified day and hour recording his reasons for such adjournment. Where a sale is so adjourned for a longer period than 7 days, a fresh proclamation under clause (i) shall be made unless the judgement debtor consents to waive it.

- (k) The property shall be paid for in cash at the time of sale, or as soon thereafter as the officer holding the sale shall appoint, and the purchaser shall not be permitted to carry away any part of the property until he has paid for it in full. Where the purchaser may fail in payment of purchase money, the property shall be resold.
- (l) Where any property which has been attached under these rules has been forcibly or clandestinely removed by any person, the Sale Officer may apply to a civil court having jurisdiction for restoration of such property. Where the court is satisfied about the truth of the facts, as alleged in the application, it may order forthwith such property to be restored to the Sale Officer.
- (m) Where prior to the day fixed for sale, the defaulter or any person acting on his behalf or any person claiming an interest in the property attached, pays the full amount due including interest, batta and other costs incurred in attaching the property, the Sale Officer shall cancel the order of attachment and release the property forthwith.
- (n) The movable properties mentioned as exempt from attachment in the proviso to section

60 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), shall not be liable to attachment or sale under these rules.

(6) Where the movable property to be attached is the salary or allowance or wages of a public servant or a servant of a local authority or a firm or a company, the Recovery Officer may, on receiving a report from the Sale Officer, order that the amount shall, subject to the Provisions of section 60 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) be withheld from such salary or allowances or wages either in one payment or by monthly instalments as the Recovery Officer may direct and upon receipt of the order, the officer or other person whose duty it is to disburse such salary or allowance or wages shall withhold and remit to the Sale Officer, the amount due under the order or the monthly instalment, as the case may be.

(7) (i) Where the property to be attached consists of the share or interest of the defaulter in movable property belonging to him and another as co-owners, the attachment shall be made by a notice to the defaulter, prohibiting him from transferring the share or interest or charging it in any way.

(ii) Where the property to be attached is negotiable instrument not deposited in a court, nor in the custody of a public officer, the attachment shall be made by actual seizure and the instrument shall be brought to the office of the Recovery Officer ordering the attachment and be held subject to his further orders.

(iii) Where the property to be attached is in the custody of any court or public officer, the attachment shall be made by a notice to such court or officer, requesting that such property and any interest or dividend becoming payable thereon may be held subject to the further orders of the Recovery Officer issuing the notice :

Provided that where such property is in the custody of a court or Recovery officer of another district, any question of title or priority arising between the decree-holder and any other person not being the defaulter, claiming to be interested in such property by virtue of any assignment, attachment or otherwise shall be determined by such court or Recovery Officer.

(8) (i) Where the property to be attached is a decree either for the payment of money or for sale in enforcement of a mortgage or charge, the attachment shall be made if the decree sought to be attached was passed by the Central Registrar or by any person to whom a dispute was transferred by the Central Registrar under section 76, then by the order of the Central Registrar.

(ii) Where the Central Registrar makes an order under clause (i) he shall on the application of the decree-holder who has attached the decree, proceed to execute the attached decree and apply the net proceeds in satisfaction of the decree sought to be executed.

(iii) The holder of a decree sought to be executed by the attachment of another decree of the nature specified in clause (i), shall be deemed to be the representative of the holder of the attached decree and to be entitled to execute such attached decree in any manner for the holder thereof.

(iv) Where to property to be attached in execution of a decree is a decree other than a decree of the nature referred to in clause (i), the attachment shall be made by the issue of a notice by the Recovery Officer to the holder of such decree, prohibiting him from transferring or charging the same in any way.

(v) The holder of a decree attached under this sub-rule shall give the Recovery Officer executing the decree such information and aid as may reasonably be required.

(vi) On the application of the holder of a decree sought to be executed by the attachment of another decree, the Recovery Officer making an order of attachment under this sub-rule shall give notice of such order to the judgment-debtor bound by the decree attached; and no payment or adjustment of the attached decree made by the judgment-debtor in contravention of such order after receipt of notice thereof, either through the said Recovery Officer or otherwise, shall be recognised so long as the attachment remains in force.

(9) Where the movable property to be attached is—

- (a) a debt due to the defaulter in question,
- (b) a share in the capital of a corporation or a deposit invested therein, or
- (c) other movable property not in the possession of the defaulter, except property deposited in or in the custody of any civil court, the attachment shall be made by a written order signed by the Recovery Officer prohibiting.
  - (i) in the case of a debt, the creditor from recovering the debt and the debtor from making payment thereof;
  - (ii) in the case of a share or deposit, the person in whose name the share or the deposit may be standing, from transferring the share or deposit or receiving any dividend or interest thereon; and

(iii) in the case of any other movable property, the person in possession of it from giving it over to the defaulter.

A copy of such order shall be sent in the case of the debt to the debtor, in the case of the share or deposit, to the proper officer of the corporation and in the case of the other movable property to the person in possession of such property. As soon as the debt referred to in clause (a) or the deposit referred to in clause (b) matures, the Recovery Officer may direct the person concerned to pay the amount to him. Where the share is not withdrawable, the Recovery Officer shall arrange for its sale through a broker. Where the share is withdrawable, its value shall be paid to the Recovery Officer or to the party referred to in clause (c). In the case of other movable property referred to in sub-clause (iii) of clause (c) the person concerned shall place it in the hands of the Recovery Officer when it becomes deliverable to the defaulter.

(10) Immovable property shall not be sold in execution of a decree unless such property has been previously attached :

Provided that where the decree has been obtained on the basis of a mortgage of such property it shall not be necessary to attach it.

(11) In the attachment and sale, or sale without attachment of immovable property, the following rules shall be observed:

- (a) The application presented under sub-rule (2) shall contain a description of the immovable property to be proceeded against, sufficient for its identification and in case such property can be identified by boundaries or numbers in a record of settlement or survey, the specification of such boundaries or numbers and the specification of the defaulter's share or interest in such property to the best of the belief of the decree-holder and so far as he has been able to ascertain it.
- (b) The demand notice issued by the Recovery Officer under sub-rule (3) shall contain the name of the defaulter, the amount due, including the expenses, if any, and the bhatta to be paid to the person who shall serve the demand notice, the time allowed for payment and in case of non-payment, the particulars of the properties to be attached and sold or to be sold without attachment, as the case may be. After receiving the demand notice, the Sale Officer shall serve or cause to be served a copy of the demand notice upon the defaulter or upon some adult

male member of his family at his usual place of residence, or upon his authorised agent or if such personal service is not possible, shall affix a copy thereof on some conspicuous part of the immovable property about to be attached and sold or sold without attachment, as the case may be :

Provided that, where the Recovery Officer is satisfied that a defaulter with intent to defeat or delay the execution proceeding against him is about to dispose of the whole or any part of his property, the demand notice issued by the Recovery Officer under sub-rule (3) shall not allow any time to the defaulter for payment of the amount due by him and the property of the defaulter shall be attached forthwith.

- (c) If the defaulter fails to pay the amount specified in the demand notice within the time allowed, the Sale Officer shall proceed to attach and sell, or sell without attachment, as the case may be the immovable property noted in the application for execution in the following manner.
- (d) Where attachment is required before sale, the sale Officer shall, if possible, cause a notice of attachment to be served on the defaulter personally. Where personal service is not possible, the notice shall be affixed in some conspicuous part of the defaulter's last known residence, if any. The fact of attachment shall also be proclaimed by beat of drum or other customary mode at some place on, or adjacent to, such property and at such other place or places as the Recovery Officer may consider necessary to give due publicity to the sale. The attachment notice shall set forth that, unless the amount due with interest and expenses be paid within the date therein mentioned, the property will be brought to sale. A copy shall be sent to the decree-holder. Where the Sale Officer so directs the attachment shall also be notified by public proclamation in the Official Gazette.
- (e) Proclamation of sale shall be published by affixing a notice in the office of the Recovery Officer and the taluk office at least thirty days before the date fixed for the sale and also by beat of drum in the village (on two consecutive days previous to the date of sale and on the day of sale prior to the commencement of the sale). Such proclamation shall, where attachment is required before sale, be made after the attachment

has been effected. Notice shall also be given to the decree-holder and the defaulter. The proclamation shall state the time and place of sale and specify as fairly and accurately as possible—

- (i) the property to be sold,
  - (ii) any encumbrance to which the property is liable,
  - (iii) the amount for the recovery of which sale is ordered, and
  - (iv) every other matter which the Sale Officer considers material for a purchaser to know in order to judge the nature and value of the property.
- (f) When any immovable property is sold under these rules, the sale shall be subject to the prior encumbrances on the property, if any. The decree-holder shall, when the amount for the realisation of which the sale is held exceeds Rs. 100, furnish to the Sale Officer within such time as may be fixed by him or by the Recovery Officer, an encumbrance certificate from the Registration Department for the period of not less than twelve years prior to the date of attachment of the property sought to be sold, or in cases falling under the proviso to sub-rule (10), prior to the date of the application for execution. The time for production of the encumbrance certificate may be extended at the discretion of the Sale Officer, or the Recovery Officer, as the case may be. The sale shall be by public auction to the highest bidder :

Provided that it shall be open to the Sale Officer to decline to accept the highest bid where the price offered appears to be unduly low or for other adequate reasons:

Provided further that the Recovery Officer or the Sale Officer may in his discretion adjourn the sale to a specified day and hour recording his reason for such adjournment. Where a sale is so adjourned for a longer period than 7 days, a fresh proclamation under clause (e) shall be made, unless the defaulter consents to waive it. The sale shall be held after the expiry of not less than thirty days calculated from the date on which notice of the proclamation was affixed in the office of the Recovery Officer. The time and place of sale shall be the village where the property to be sold is situated or such adjoining promi-

nent place of public resort as may be fixed by the Recovery Officer :

Provided also that in cases where an encumbrance certificate is not obtainable owing to the destruction of the connected records an affidavit from the village patwari or corresponding officer in regard to the encumbrances known to him supported by a certificate from the Registration Department that the encumbrance certificate cannot be granted owing to the destruction of the connected records, shall be accepted in place of an encumbrance certificate.

- (g) A sum of money equal to 15 per cent of the price of the immovable property shall be deposited by the purchaser in the hands of the Sale Officer at the time of the purchase, and in default of such deposit, the property shall forthwith be resold :

Provided that, where the decree-holder is the purchaser and is entitled to set off the purchase money under clause (k), the Sale Officer shall dispense with the requirements of this clause.

- (h) The remainder of the purchase money and the amount required for the general stamp for the sale certificate shall be paid within fifteen days from the date of sale :

Provided that, the time for payment of the cost of the stamps may, for good and sufficient reasons, be extended at the discretion of the Recovery Officer up to thirty days from the date of sale :

Provided further that, in calculating the amounts to be paid under this clause, the purchaser shall have the advantage of any set off to which he may be entitled under clause (k).

- (i) In default of payment within the period mentioned in clause (h) the deposit may, if the Recovery Officer thinks fit, after defraying the expenses of the sale, be forfeited to the Central Government and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may subsequently be sold.
- (j) Every resale of immovable property in default of payment of the amounts mentioned in clause (h) within the period allowed for such payment, shall be made after the issue of a fresh proclamation in the manner and for the period herein before prescribed for the sale.

- (k) Where a decree-holder purchases the property, the purchase money and the amount due on the decree shall be set off against one another, and the Sale Officer shall enter satisfaction of the decree in whole or in part accordingly.

(12) Where prior to the date fixed for a sale, the defaulter or any person acting on his behalf or any person claiming an interest in the property sought to be sold tenders payment of the full amount due together with interest, bhatta and other expenses incurred in bringing the property to sale including the expenses of attachment, if any, the Sale Officer shall for with release the property after cancelling, where the property has been attached, the order of attachment.

(13)(i) Where immovable property has been sold by the Sale Officer, any person either owning such property or holding an interest therein by virtue of a title acquired before such sale may apply to have the sale set aside on his depositing with the Recovery Officer.—

- (a) for payment to the purchaser a sum equal to 5 per cent of the purchase money, and

- (b) for payment to the decree-holder, the amount of arrears specified in the proclamation of sale as that for the recovery of which the sale was ordered together with interest thereon and the expenses of attachment, if any, and sale and other costs due in respect of such amount, less amount which may since the date of such proclamation have been received by the decree-holder.

(ii) If such deposit and application are made within thirty days from the date of sale the Recovery Officer shall pass an order setting aside the sale and shall repay to the purchaser, the purchase money so far as it has been deposited, together with 5 per cent deposited by the applicant :

Provided that, if more persons than one have made deposit and application under this sub-rule the application of the first depositor to the officer authorised to set aside the sale, shall be accepted.

(iii) If a person applies under sub-rule (14) to set aside the sale of immovable property, he shall not be entitled to make an application under this sub-rule.

14. (i) At any time within thirty days from the date of the sale of immovable property, the decree-holder or any person entitled to share in a rateable distribution of the assets or whose interests are affected by the sale, may apply to the Recovery Officer to set aside the sale on the ground of a material irre-

gularity or mistake or fraud in publishing or conducting it :

Provided that, no sale shall be set aside on the ground of irregularity or fraud unless the Recovery Officer is satisfied that the applicant has sustained substantial injury by reason of such irregularity, mistake or fraud.

(ii) If the application be allowed, the Recovery Officer, shall set aside the sale and may direct a fresh one.

(iii) On the expiration of thirty days from the date of sale if no application to have the sale set aside is made or if such application has been made and rejected the Recovery Officer shall make an order confirming the sale :

Provided that, if he shall have reason to believe that the sale ought to be set aside notwithstanding that no such application has been made or on grounds other than those alleged in any application which has been made and rejected, he may, after recording his reasons in writing, set aside the sale.

(iv) Whenever the sale of any immovable property is not so confirmed or is set aside, the deposit or the purchase money, as the case may be shall be returned to the purchaser.

(v) After the confirmation of any such sale, the Recovery Officer shall grant a certificate of sale bearing his seal and signature to the purchaser, and such certificate shall state the property sold and the name of the purchaser and it shall be conclusive evidence of the fact of the purchase in all courts and tribunals, where it may be necessary to prove it and no proof of the seal or signature of the Recovery Officer shall be necessary unless the authority before whom it is produced shall have reason to doubt its genuineness.

(vi) An order made under this sub-rule shall be final, and shall not be liable to be questioned in any suit or other legal proceedings.

(15) Where any lawful purchaser of immovable property is resisted and prevented by any person other than a person (not being the defaulter) claiming in good faith to be in possession of the property on his own account from obtaining possession of the immovable property purchased, any court of competent jurisdiction on application, and production of the certificate of sale provided for by sub-rule (14) shall cause the proper process to be issued for the purpose of putting such purchaser in possession, in the same manner as if the immovable property purchased had been decreed to the purchaser by a decision of the court,

(16) It shall be lawful for the Sale Officer to sell the whole or any portion of the immovable property of a defaulter in discharge of money due :

Provided that so far as may be practicable, no larger section or portion of immovable property shall be sold than may be sufficient to discharge the amount due with interest and expenses of attachment, if any, and sale.

(17) Persons employed in serving notice or in other process under these rules shall be entitled to bhatta at such rates as may from time to time be fixed by the Recovery Officer.

(18) Where the cost and charges incurred in connection with attachment and sale of movable property or the attachment and sale or sale without attachment of immovable property under this rule, exceeds the amount of the cost deposited by the decree-holder under sub-rule(1) such excess shall be deducted from the sale proceeds of the property sold or the moneys paid by defaulter, as the case may be, and the balance shall be made available to the decree-holder.

(19) Every person making a payment towards any money due for the recovery of which application has been made under this rule shall be entitled to a receipt for the amount signed by the Sale Officer or other officer empowered by the Recovery Officer in that behalf; such receipt shall state the name of the person making the payment and the subject matter in respect of which the payment is made.

(20) (a) Where any claim is preferred to, or any objection is made to the attachment of, any property attached under this rule on the ground that such property is not liable to such attachment, the Sale Officer shall investigate the claim or objection and dispose of it on the merits :

Provided that no such investigation shall be made when the sale officer considers that the claim or objection is frivolous.

(b) Where the property to which the claim or objection relates has been advertised for sale, the Sale Officer may postpone the sale pending the investigation of the claim or objection.

(c) Where a claim or an objection is preferred, the party against whom an order is made may institute a suit to establish the right which he claim to the property in dispute, but, subject to the result of such suit, if any, the order shall be conclusive.

(21) (i) any deficiency of price which may arise on a re-sale held under clause (j) of sub-rule (11) by reason of the purchaser's default and all expenses attending such re-sale shall be certified by the Sale Officer to the Recovery Officer and shall, at the instance of either the decree-holder or the defaulter

be recoverable from the defaulting purchaser under the provisions of this rule. The costs, if any incidental to such recovery shall be borne by the defaulting purchaser.

(ii) Where the property may on the second sale, sell for a higher price than at the first sale, the defaulting purchaser at the first sale, shall have no claim to the difference or increase.

(22) Where any property has been attached in execution of a decree, but by reason of the decree-holder's default the Recovery Officer is unable to proceed further with the application for execution, he shall either dismiss the application or for any sufficient reason adjourn the proceeding to a future date. Upon the dismissal of such application, the attachment shall cease.

(23) Where assets are held by the Sale Officer and before the receipt of such assets, demand notices in pursuance of application for execution of decree against the same defaulter have been received from more than one decree-holder and the decree-holders have not obtained satisfaction, the assets after deducting the costs or realisation, shall be rateably distributed by the Sale Officer among all such decree-holders in the manner provided in section 73 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(24) Where a defaulter dies before the decree has been fully satisfied, an application under sub-rule (1) may be made against the legal representative of the deceased and thereupon all the provision of this rule shall, save as otherwise provided in this sub-rule, apply as if such legal representative were the defaulter. Where the decree is executed against such legal representative, he shall be liable only to the extent of the property of the deceased which has come to his hands and has not been duly disposed of; and for the purpose of ascertaining such liability, the Recovery Officer executing the decree may, of his own motion or on the application of the decree-holder compel such legal representative to produce such accounts as he thinks fit.

23. Mode of making attachment before judgment.—(1) Attachment of property under section 87 shall be made in the manner provided in rule 22.

(2) Where a claim is preferred to property attached under sub-rule (1) such claim shall be investigated in the manner and by the authority specified in rule 22.

(3) Where a direction is made for the attachment of any property under sub-rule (1), the Recovery Officer shall order the attachment to be withdrawn—

- (a) when the party concerned furnishes the security required, together with the security for the costs of the attachment; or

(b) when the liquidator determines under clause (b) of sub-section (2) of section 81 that no contribution is payable by the party concerned; or

(c) when the Central Registrar passes an order under sub-section (1) of section 73 that the party concerned need not repay or restore any money or property or contribute any sum to the assets of the society by way of compensation; or

(d) when the dispute referred to in sub-section (1) of section 76 has been decided against the party at whose instance the attachment was made.

(4) Attachment made under sub-rule (1) shall not affect the right existing prior to the attachment of persons not parties to the proceedings in connection with which the attachment was made, nor bar any person holding a decree against the person whose property is attached from applying for the sale of the property under attachment in execution of such decree.

(5) Where property is under attachment by virtue of the provisions of this rule and a decree is subsequently passed against the person whose property is attached, it shall not be necessary upon an application for execution of such decree to apply for re-attachment of the property.

24. Mode of service of summon.—(1) Every summons issued under the Act or these rules shall be in writing, shall be authenticated by the seal, if any, of the officer by whom it is issued and shall be signed by such officer or by any person authorised by him in writing in that behalf. It shall require the person summoned to appear before the said officer at a stated time and place, and shall specify whether his attendance is required for the purpose of giving evidence, or to produce a document, or for both purposes; and any particular document the production of which is required, shall be described in the summons with reasonable accuracy.

(2) Any person may be summoned to produce a document, without being summoned to give evidence; and any person summoned merely to produce a document shall be deemed to have complied with the summons if he causes such document to be produced, instead of attending personally to produce the same.

(3) The service of summons under the Act or these rules on any person, may be effected in any of the following ways :—

- (a) by giving or tendering it to such person; or
- (b) if such person is not found, by leaving it at his last known place of abode or business or

by giving or tendering it to some adult member of his family; or

(c) if the address of such person is known to the Central Registrar or other authorised person by sending it to him by registered post acknowledgement due; or

(d) if none of the means aforesaid is available, by affixing it in some conspicuous part of his last known place of abode or business.

(4) Where the serving officer delivers or tenders a copy of the summons to the defendant personally or to an agent or other person on his behalf, he shall require the signature of the person to whom the copy is so delivered or tendered as an acknowledgement of service endorsed on the original summons.

(5) The serving officer shall in all cases in which the summons have been served under sub-rule(4), endorse or annex, or cause to be endorsed or annexed, on or to the original summons a return stating the time when and the manner in which the summons was served and the name and address of the person, if any, identifying the person served and witnessing the delivery or tender of the summons.

(6) Where the defendant to be summoned is a public officer or is a servant of a company or a local authority, the officer issuing the summons may, if it appears that the Summons may be conveniently so served, send it by registered post acknowledgement due for service on the party to be summoned, to the head of the office in which he is employed together with a copy to be retained by the defendant.

#### CHAPTER VI

#### SOCIETIES WHICH BECOME MULTI-STATE CO-OPERATIVE SOCIETIES CONSEQUENT ON REORGANISATION OF STATES.

25. Preparation of a scheme for the reconstitution or reorganisation of multi-State co-operative societies.

(1) The Central Registrar or an authorised officer, shall prepare a scheme referred to in sub-section (2) of section 95 for the reconstitution or reorganisation of any multi-State co-operative society rendered as such, consequent on the reorganisation of the States and referred to in sub-section (1) of section 95, and forward a copy of the scheme to the President or the Chairman of the multi-State co-operative society with the direction that the scheme be placed before a meeting of the general body of the multi-State co-operative society specially convened for the purpose.

(2) The meeting referred to in sub-rule (1) shall be convened not less than 40 days after the date of issue of the notice to the members and the creditors of the multi-State co-operative society in the manner specified in sub-rule (3).

(3) A written notice specifying the date, hour and place of meeting and the business to be transacted there at shall be given to every member and shall be accompanied by a copy of the scheme to be considered at the meeting. The notice to each member and creditor shall.—

(i) be delivered or tendered to him in person;

(ii) be sent to him by registered post; or

(iii) be served on him in such other manner as may be specified in the bye-laws of the society.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any rule or bye-law governing the multi-State co-operative society, where the Central Registrar or the authorised officer in this behalf is satisfied that the President or Chairman of the society has failed to convene the special meeting as required under sub-rule(1), the Central Registrar or the authorised officer, as the case may be, shall convene a meeting of the general body of the multi-State Co-operative Society by giving 14 days notice to all the members and creditors of the multi-State Co-operative Society.

#### CHAPTER VII

#### MISCELLANEOUS

26. Address of a multi-State co-operative society. The bye-laws of every multi-state co-operative society shall contain the address of the society to which all notices and communications may be sent. The address of the multi-State co-operative society shall include the name of the State, the district, post office and the village or town. Any change in the address of the multi-State co-operative society shall be communicated to the Central Registrar within a month of such change.

27. Repeal and savings. (1) The Multi-Chit Co-operative societies Rules, 1958 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the rules so repealed shall, unless such thing or action is inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of these rules.

[No. L-11012/1/84-L&M]

K. N. ARDHANAREESWARAN, Addl. Secy.